

विश्वास वो ताकत है, जो
उजड़ी हुई
जिंदगी में भी रोशनी भर
देती है!

03 जेल में बंद केजरीवाल... बाहर पत्नी ने ले लिया ये फैसला, दिल्ली में सबसे बड़ा सियासी उलटफेर! 06 जल संकट से जूझता प्रदेश 08 मोदी गठबंधन के अग्निपथ पर अब 9 को लेंगे शपथ

क्या कश्मीरी गेट बस अड्डे के अंदर से स्टेज कैरिज एवं राजकीय बस सेवा के साथ आल इंडिया परमिट की बसों को चलाने की इजाजत देने से, जनता रहेगी सुरक्षित, बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग जिसका पहला दायित्व है जनता को विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी सवारी वाहन सेवा उपलब्ध करवाना, अपना दायित्व भुल कर और जनता की सुरक्षा को दाव पर लगाकर सिर्फ राजस्व बढ़ोतरी में स्लगन है। जिन वाहनों को अब तक परिवहन विभाग और परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा डमगामार बता कर बंद करने की लिए सदा तत्पर रहने का दिखावा करती थी आज उन्हीं बसों को परिवहन विभाग द्वारा जनता के सबसे विश्वसनीय बस अड्डे के अंदर से सवारी उतारने और चढ़ाने की इजाजत दे दी हुई है और वह भी सिर्फ पार्किंग के नाम से पैसा वसूलने के लिए यानी राजस्व कमाने के लिए यानी जनता की सुरक्षा को दाव पर लगा कर राजस्व कमाने के लिए पहले ही परिवहन विभाग ने पिछले 12 सालों में

सरकारी राजस्व खर्च कर दिल्ली परिवहन निगम (जनता को सुरक्षित, विश्वसनीय, समयानुसार और आराम दायक सवारी सेवा प्रदान करने वाला सरकारी निकाय) को एक भी बस खरीद कर नहीं दी। यहां एक बात और आप सबके लिए जाने योग्य है की भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक सवारी सेवा के लिए बसें खरीदने की लिए जो भी सब्सिडी प्रदान करी गई उसे प्राप्त करने के बाद भी दिल्ली परिवहन निगम के नाम पर बसें लेने की जगह प्राइवेट कंपनियों से बसें लेकर जनता को गुमराह करने के लिए घोषणा में डीटीसी के बड़े में इतनी बसें आज शामिल कहते रहे। * इस बात की पुष्टि जांच के लिए कोई भी आरटीआई के माध्यम से दिल्ली परिवहन विभाग से दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के नाम आज की तारीख में कितनी बसें



पंजीकृत हैं लगा कर जान सकता है और साथ ही यह भी जान सकता है की दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के नाम पर आखिरी बस किस वर्ष में खरीदी गई थी दिल्ली परिवहन विभाग ने जनता को सार्वजनिक सवारी सेवा प्राप्त

करने के लिए किए जाने वाले इंतजार के लिए जो बस क्यू शेल्टर उपलब्ध करवाने होते हैं वह भी पिछले 10 वर्षों में नहीं बनवाए जब की बस क्यू शेल्टर के प्रयोग करने के नाम से बिना बस क्यू शेल्टर उपलब्ध करवाए क्लस्टर कंपनियों और

प्राइवेट स्टेज कैरिज बस परमिट धारकों से करोड़ों रुपए वसूले और करोड़ों का बकाया भुगतान का दबाव बनाया हुआ है। जनहित और जनता को सुखद सेवा प्रदान करवाने के उद्देश्य से बनाया गया सरकारी विभाग और उसमें कार्यरत

आला अधिकारी अगर अपने ध्येय से हट कर राजस्व वसूली और साम दाम दण्ड भेद से राजस्व के इजाफे में लग जाए तो जनता को सुखद, सुरक्षित, विश्वसनीय और आराम दायक सार्वजनिक सवारी सेवा कैसे उपलब्ध

हो सकती है, बड़ा सवाल ? है क्या आप में से किसी के पास इसका जवाब अब जनता ही बताएं अगर रक्षक के पद पर भक्षक बैठ जाए तो क्या जिस दायित्व के लिए वह विभाग बना वह अपना दायित्व पूरा करेगा ?

बाहर मौसम गर्म है: दिल्ली एनसीआर में मेट्रो बनी हमसफर मीषण गर्मी में तोड़ा मई का भी रिकॉर्ड; देखें आंकड़े

परिवहन विशेष न्यूज

सूर्य की तपिश में मेट्रो हमसफर बनी हुई है। मेट्रो के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनुज दयाल ने बताया कि इस बार मई में मेट्रो में प्रतिदिन 60.17 लाख यात्राएं यात्रियों ने की है। पिछले वर्ष मई में यह आंकड़ा 52.41 लाख था।

नई दिल्ली। मीषण गर्मी में दिल्ली-एनसीआर के लोग मेट्रो को यात्रा के लिए अपना हमसफर बना रहे हैं। यही कारण है कि बीते वर्ष के मई माह की तुलना में इस बार मई में प्रतिदिन औसत पैसेंजर जर्नी (यात्रियों की यात्राएं) 7.76 लाख अधिक रही। वर्ष 2022 के मई माह में औसत पैसेंजर जर्नी 39.4 लाख थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि रिकॉर्ड गर्मी के बीच दिल्ली मेट्रो बिना किसी रुकावट के वातानुकूलित आरामदायक यात्रा की सुविधा पूरे नेटवर्क पर उपलब्ध करा रहा है। गर्मी के मद्देनजर मेट्रो में एसी समेत अन्य उपकरणों की निगरानी बढ़ाई गई है।

मेट्रो के प्रतिदिन 4200 फेरे दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों ने बताया कि मौजूदा समय में मेट्रो ट्रेनें प्रतिदिन 4200 फेरे लगा रही हैं और एक लाख 40 किलोमीटर सफर तय करती हैं। मेट्रो के नेटवर्क में मौजूद 345 ट्रेनों में 5000 एसी यूनिट लगाई गई हैं। हर वर्ष गर्मी से पहले माच में मेट्रो के एसी की व्यापक स्तर पर तकनीकी जांच व रखरखाव का किया जाता है। इस दौरान



खराब उपकरण बदले जाते हैं।

मई में 60.17 लाख यात्रियों ने की यात्रा

इसके अलावा हर तीन माह पर नियमित रखरखाव का काम होता है। चालक भी मेट्रो के तापमान पर नियमित निगरानी रख रहे हैं। मेट्रो के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अनुज दयाल ने बताया कि इस बार मई में मेट्रो में प्रतिदिन 60.17 लाख यात्राएं यात्रियों ने की है। पिछले वर्ष मई में यह आंकड़ा 52.41 लाख था। इसका कारण यह है कि एक लो कोराना के बाद मेट्रो में वापस यात्रियों की

संख्या लगातार बढ़ी है, दूसरी बात यह कि गर्मी में लोग मेट्रो में सफर करना बेहतर समझ रहे हैं।

तकनीक से तापमान को किया जाता है नियंत्रित

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली मेट्रो के सभी भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) व चिलर प्लांट मैनेजर (सीपीएम) जैसे अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। इसके जरिये भूमिगत स्टेशनों पर लगे सेंट्रलाइज एसी की निगरानी की जाती है और तापमान को नियंत्रित रखा

जाता है। इसलिए बाहर 45 से 50 डिग्री तापमान रहने पर भी स्टेशन का तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। वहीं मेट्रो ट्रेनों में पूरे दिन तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मेट्रो में ब्रेक डाउन, मेट्रो ट्रेन या भूमिगत मेट्रो स्टेशन में एसी फेल्टोर की घटनाएं नहीं हुईं।

आग से सुरक्षा के हैं व्यापक इंतजाम

मीषण गर्मी के चलते दिल्ली मेट्रो के एस्केलेटर, लिफ्ट सहित अन्य गर्म होने वाले सभी उपकरणों की निगरानी बढ़ाई गई है। आग से बचाव के लिए अग्निशामक यंत्र,

संप्रिंक्लर, पानी की पाइप व अन्य जरूरी आग से बचाव के उपकरण हैं। इसका नियमित रखरखाव किया जाता है। ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी इस्तेमाल किया जा सके।

साथ ही स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को आपात स्थिति में राहत बचाव का प्रशिक्षण भी समय-समय पर दिया जाता है। मेट्रो में आग लगने की स्थिति में अलार्म तकनीक अत्याधुनिक है। अभी तक दिल्ली मेट्रो के किसी भी ट्रेन में आग लगने जैसे स्थिति नहीं हुई है।

दिल्ली भारत देश की राजधानी में सड़को और बस क्यू शेल्टर के आगे के कुछ दृश्य, जिनके बल पर चलती है बसें अपनी अधिकृत लाइनों में



टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

पर्यावरण पाठशाला - वट सावित्री पूजा: महत्व और उत्सव

अंकुर

वट सावित्री पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। इस पूजा का प्रमुख उद्देश्य अपने पति की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करना है। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन देश के अन्य भागों में भी इसे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है।

वट सावित्री पूजा का महत्व
वट सावित्री पूजा का मुख्य आधार पौराणिक कथा है जिसमें सावित्री के अटूट प्रेम और समर्पण का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार, सावित्री ने अपने पति सत्यवान की अकाल मृत्यु के बाद अपने दुःख संकल्प और भक्ति से यमराज से अपने पति का जीवन वापस प्राप्त किया था। इसी कथा के आधार पर इस व्रत का प्रचलन हुआ, जिसमें वट (बरगद) वृक्ष का विशेष महत्व है। वट वृक्ष को अक्षय वट भी कहा जाता है, जो दीर्घायु और स्थायित्व का प्रतीक है।

पूजा की विधि
वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन, महिलाएं सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं और पूजा की तैयारी करती हैं। वट वृक्ष के पास जाकर महिलाएं उसकी जड़ में जल अर्पित करती हैं और धागा बांधती हैं। इसके बाद, सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर कथा का श्रवण करती हैं। पूजा के दौरान, वट वृक्ष की सात परिक्रमा की जाती है और सावित्री का ध्यान किया जाता है।

पूजा का महत्व और लाभ
इस व्रत का आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों ही



दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व है। आध्यात्मिक रूप से, यह पूजा महिलाओं को अपने पति के प्रति प्रेम, समर्पण और निष्ठा को प्रकट करने का अवसर प्रदान करती है। सामाजिक दृष्टिकोण से, यह व्रत परिवार और समाज में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका और उनकी शक्ति को मान्यता देता है। इस व्रत को करने से पति की दीर्घायु, सुख-समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, ऐसा विश्वास है।

उत्सव का माहौल
वट सावित्री पूजा का माहौल अत्यंत उत्साहपूर्ण और श्रद्धापूर्ण होता है। महिलाएं सांझे परिधान और आभूषण पहनकर इस पूजा में भाग लेती हैं। कई

स्थानों पर महिलाएं सामूहिक रूप से वट वृक्ष के पास इकट्ठा होकर पूजा करती हैं, जिससे सामूहिक एकता और भाईचारे की भावना को भी बल मिलता है। वट सावित्री पूजा भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न हिस्सा है। यह पूजा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि परिवार और समाज में सद्भाव और एकता को भी बढ़ावा देती है। सावित्री के अद्वितीय प्रेम और समर्पण की इस कथा से प्रेरणा लेकर महिलाएं अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और समर्पण का संचार करती हैं। फरीदाबाद के स्वामी विवेकानंद पार्क,

संलग्न फील्ड सेक्टर 31 में स्थित वट वृक्ष की अनुपम छटा देखने को मिलती है। प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित यह पार्क संस्कार का सुंदर केंद्र है। वट वृक्ष के विशाल और घने छत्र के नीचे बैठकर शांति और सुकून का अनुभव किया जा सकता है। यहां की हरियाली और स्वच्छ वातावरण मन को प्रसन्नता और ताजगी प्रदान करते हैं। स्वामी विवेकानंद पार्क न केवल मनोरंजन का स्थल है, बल्कि यह शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

indiangreenbuddy@gmail.com

सावधान! चिलचिलाती गर्मी से लोग बेहाल, अब डेंगू ने दी दस्तक; तीन लोगों में मिली संक्रमण की पुष्टि

जिले में इस समय गर्मी से लोग परेशान हैं तो अब गर्मी के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। अभी तक तीन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से संदिग्ध मरीजों की सैपलिंग जारी है। 31298 घरों का सर्वे किया जा चुका है। अब तक 314 सैपल लिए गए हैं। विशेषज्ञों की माने तो डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में पनपता है

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम। जिले में गर्मी के बीच डेंगू ने दस्तक दे दी है। गुरुवार को डीएलएफ सिटी फेज-2 और सेक्टर 53 स्थित गांधी नगर के तीन लोगों की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक 31298 घरों का सर्वे किया जा चुका है। जबकि, 314 सैपल लिए गए हैं। इसके अलावा डायरिया के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से घर-घर सर्वे जारी है। डेंगू के खतरे की आशंका को लेकर संदिग्ध लोगों की सैपल लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को डेंगू के प्रकोप से बचाव उपाय बताने के साथ-साथ कूलर, गमले, फ्रीज ट्रे, टायर, ट्यूब, नाद आदि हर छोटी-बड़ी जगह की भरे पानी को साफ करने और सावधानी बरतने की अपील की जा रही है।

सैपल लेते स्वास्थ्यकर्मी

विशेषज्ञों की माने तो डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में पनपता है। इसका वाहक एडीज मच्छर है, जो दिन के समय कार्टता है। डेंगू के सामान्य मामलों में बुखार का चोचा से सातवां दिन बेहद खतरनाक होता है।

पहले दिन से लेकर पांच दिन तक सिर्फ एनएसवन टेस्ट पाजीटिव आता है, जबकि पांच



दिनों के बाद एलाइजा टेस्ट पाजीटिव आता है। विगत दो वर्षों से डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। गत वर्ष डेंगू के करीब 440 मामले सामने आए थे, जबकि डेंगू से एक मौत भी दर्ज की गई।

इस बात का रहे ध्यान

अगर डेंगू के लक्षण दिख रहे हैं तो चिकित्सक की निगरानी में इलाज कराएं। खुद से चिकित्सा करने का प्रयास न करें। अगर किसी लैब में जांच के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा

निर्धारित मूल्य से ज्यादा की वसूली की जा रही है तो भी स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें।

निजी अस्पतालों में टेस्ट के रेट निर्धारित प्रदेश सरकार ने जिला में सभी प्राइवेट अस्पतालों तथा लैब में डेंगू व चिकनगुनिया की जांच के लिए 600 रुपये निर्धारित किये हैं। वहीं चिकनगुनिया के आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए 1000 रुपये निर्धारित किये गए हैं। डीएलएफ सिटी फेज-2 और सेक्टर 53 स्थित गांधी नगर के

तीन लोगों की रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। गुरुवार को टीम ने शहरी क्षेत्रों में 16128 और ग्रामीण क्षेत्रों में 15170 घरों का सर्वे किया। इसमें सात संदिग्ध लोगों के सैपल लिए गए हैं। जबकि, छह लोगों को लार्वा मिलने पर नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 10 घरों में और 23 कंटेनरों में लार्वा मिला। इसे टीम ने मौके पर ही नष्ट किया।

डा. जयप्रकाश, जिला मलेरिया अधिकारी

अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से दो लोगों की मौत, आरोपी चालक फरार; पुलिस कर रही तलाश



दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर मुरादनगर में पेट्रोल पंप के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ। जिसमें अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से गुरुवार को दो लोगों की मौत हो गई। ट्रक चालक घटना के बाद से मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जगह-जगह पर छापेमारी कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

मुरादनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर मुरादनगर में पेट्रोल पंप के निकट अनियंत्रित ट्रक की टक्कर से

गुरुवार को दो लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित ट्रक ने पहले एक बाइक में टक्कर मारी, जिस पर चालक दिल्ली के ब्रह्मपुरी का गौरव था। अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित थोड़ी ही दूरी पर पैदल चल रहे मुरादनगर की देवदत्त कालोनी के रामकुमार को टक्कर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। आरोपी फरार, पुलिस कर रही तलाश आरोपित चालक ट्रक मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक कब्जे में ले लिया है। आरोपित को तलाश की जा रही है। शव पोस्टमार्टम को भेज दिये गए हैं।

चुनाव में अधिकारियों ने सपा के एजेंट के रूप में किया काम, सीएम योगी से करेंगे शिकायत; भाजपा नेता का बड़ा आरोप

लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रदेश के अधिकारियों पर लोकसभा चुनाव में सपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत चुनाव के समय पुलिस अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर गई ताकि कुर्मी समाज के लोग भाजपा के खिलाफ जाएं। जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो।

साहिबाबाद। लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने प्रदेश के अधिकारियों पर लोकसभा चुनाव में सपा के एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि षड्यंत्र के तहत

चुनाव के समय पुलिस अंबेडकर नगर में सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर गई, ताकि कुर्मी समाज के लोग भाजपा को खिलाफ जाएं।
आचार संहिता के दौरान अपराध बढ़ा

जिस पुलिस अधिकारी ने ऐसा किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि शत्रुियों को भाजपा के खिलाफ करने के लिए मोटा पैसा खर्च किया गया। आचार संहिता के दौरान 90 के दशक के तरह अपराध बढ़ा।

इसमें भी अधिकारियों का हाथ रहा। गाजियाबाद में अधिकारियों की साजिश की वजह से भाजपा के डेढ़ लाख वोट नहीं पड़े। प्रधानमंत्री की वाहवाही न हो जाए इस वजह से किसान आंदोलन को हवा

दिया गया।

इस संबंध में उनके पास भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैट और एक खिलाफ जाएं।
इन सभी पहलुओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे।

महेश शर्मा की हैट-ट्रिक, अतुल गर्ग भी जीते

उत्तर प्रदेश के महासमर में एनसीआर से जुड़ी सभी छह सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसमें गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत व बुलंदशहर सीट पर भाजपा ने शुरू से दबदबा बना रखा। जबकि, अमरोहा व मेरठ संसदीय सीट पर पूरे दिन उठापटक चलती रही। देर शाम आए परिणाम में भाजपा ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की।

यूपी में OBC मैरिज ग्रांट को लेकर आया अपडेट, आय सीमा में हुआ बदलाव; इन बातों का रखना होगा ख्याल

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पिपूषू राय ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये के चलते पात्र आवेदक नहीं मिल रहे थे। अब शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दी गई है। शादी अनुदान के लिए पात्रों अभ्यर्थी को 20 हजार रुपये से लाभान्वित किया जाएगा।

गाजियाबाद। पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना के तहत शादी अनुदान के लिए आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये

की गई है। उक्त जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पिपूषू राय ने बताया कि एनसीआर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में वार्षिक आय 46080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये के चलते पात्र आवेदक नहीं मिल रहे थे।

यही कारण था कि लोग योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब शादी अनुदान का लाभ लेने के लिए सालाना आय सीमा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक कर दी गई है।

शादी अनुदान के लिए पात्रों अभ्यर्थी को 20 हजार रुपये से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में 99 का लक्ष्य है, जिसके लिए अभी तक 49 लाभार्थियों

के लिए धनराशि आई है।

आवेदन के लिए यह कागजात जरूरी आवेदक को पुत्री की आयु 18 वर्ष की तिथि को 18 वर्ष वर की आयु 21 वर्ष से अधिक। आवेदक की आय एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए। पहचान पत्र की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, विवाह का प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पुत्री की आयु से संबंधित प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक के फोटो।

मोदी ब्रांड की छवि पर जो आघात हुआ है, उससे देश ही नहीं दुनिया भी हैरान है

नौरज कुमार दुबे

भाजपा की सीट घटने से सिर्फ पार्टी के ही नेता हैरान और परेशान नहीं हैं बल्कि कई विदेशी नेता भी इस बात से हैरान हैं कि दिन-रात अपने देश के लिए काम करते रहने वाले प्रधानमंत्री को चुनावों में जनता ने क्यों सजा दे दी है।

भारत की राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दशक काफी बड़े और कड़े फैसलों वाला रहा और उनके निर्णयों और नेतृत्व की धमक देश में ही नहीं पूरी दुनिया में रही जिसके चलते वह समूचे विश्व में सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभरे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम उनके लिए आश्चर्य लेकर आये जब उनकी पार्टी भाजपा ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया और सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पर निर्भर हो गयी। इन चुनाव परिणामों ने मोदी के लिए भारत में उनके जाने वाले नेता की छवि पर बहुत बड़ा असर डाला है जिसकी गूँज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है। देखा जाये तो भारत में तो विपक्ष मोदी का राजनीतिक रूप से नुकसान पहुँचाना चाहता था साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसी शक्तियाँ थीं जो कि मोदी की रलोबल लीडर के रूप में पुख्ता होती छवि को नुकसान पहुँचाना चाहती थीं। कह सकते हैं कि भारत में विपक्ष को और विदेशों में भारत विरोधी शक्तियों को कहीं ना कहीं अपने मिशन में थोड़ी-बहुत कामयाबी मिल गयी है। लेकिन यह भी सत्य और एक तथ्य है कि मोदी की कार्यशैली मकखन पर नहीं अपितु पत्थर पर लकीर खींचने की है इसलिए वह तीसरे कार्यकाल में अपने कामकाज से विरोधियों को तगड़ा जवाब अवश्य ही देते।

चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि 'अबकी बार 400 पार' के नारे की ही नहीं बल्कि 'मोदी है तो मुमकिन है' और 'जो राम को लाये हैं हम उनको लाएंगे' जैसे नारों की भी हवा पूरी तरह निकल गयी है। चुनाव प्रचार की बात हो या भाजपा के अधिकारियों में किये जा चुके हैं, सब कुछ 'मोदी की गारंटी' के ही इर्दगिर्द केंद्रित था इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी ब्रांड की छवि पर सीधा असर पड़ा है। इसलिए अब समय आ गया है जब भाजपा को सिर्फ मोदी नाम के सहारे रहने की बजाय और भी पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। जबसे मोदी केन्द्र की राजनीति में आये हैं तबसे यही देखने को मिलता है कि पंचायत से



लेकर संसद तक के चुनाव पर भाजपा सिर्फ मोदी नाम के सहारे ही रहती है। भाजपा ने चुनाव में 'मोदी की गारंटी' के अलावा 'विकास भी और विरासत भी' का नारा दिया था और करोड़ों लोगों के गरीबी रेखा से बाहर निकलने तथा भारत के सांस्कृतिक गौरव की बहाली की दिशा में उठाये गये कदमों का हवाला दिया था फिर भी वह स्पष्ट बहुमत से बहुत दूर रह गयी। दूसरी ओर, भाजपा की सीट घटने से सिर्फ पार्टी के ही नेता हैरान और परेशान नहीं हैं बल्कि कई विदेशी नेता भी इस बात से हैरान हैं कि दिन-रात अपने देश के लिए काम करते रहने वाले प्रधानमंत्री को चुनावों में जनता ने क्यों सजा दे दी है। आप दुनिया भर की समाचार वेबसाइटों को देखेंगे तो सभी ने मोदी की सीटें घटने पर हैरानी जताई है। इन चुनाव परिणामों ने मोदी के विदेशों में रूतबे को निश्चित रूप से प्रभावित किया है। दरअसल, जिस तरह का माहौल बनाया गया था उसमें ना तो देश में और ना ही दुनिया में किसी को इस तरह के चुनाव परिणामों की अपेक्षा थी। यही कारण है कि भाजपा तो अपने चुनावी प्रदर्शन पर बहुत दूर रही है दुनिया के भी कई बड़े नेता भारत के चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं।

हम आपको यह भी बता दें कि साल 2024 में दुनिया के अधिकांश देशों में चुनाव होने हैं। कई छोटे-बड़े देशों में जून महीने की शुरुआत तक चुनाव हो चुके हैं और अमेरिका सहित कई अन्य देशों में चुनाव इस साल के अंत से पहले होने हैं। एक खास बात यह है कि अब तक जितने देशों में चुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर में सरकारें वापस सत्ता में नहीं लौटी हैं लेकिन मोदी दस साल राज करने के बाद भी तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में

लौट आये हैं। भले उनकी सीटों की संख्या कम हो गयी है लेकिन काम करने के लिए उनके पास स्पष्ट जनादेश है। मोदी ने जब 2014 में भारत सरकार की कमान संभाली थी तबसे दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्रध्यक्ष बदल चुके हैं लेकिन मोदी सत्ता में कायम हैं जिसका सीधा मतलब यही है कि जनता को उनके नेतृत्व और उनकी नीतियों में विश्वास है। यह विश्वास ही तो है कि विपक्ष के घोषणापत्र में की गयी प्री की तमाम सौगातों की बजाय जनता ने मोदी के वादों को तवज्जो दी है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक की बात करें तो उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हार-जीत राजनीति का हिस्सा है और नंबरगेम चलता रहता है। उन्होंने कहा है कि लेकिन इस सबका असर देश के विकास पर नहीं पड़ना चाहिए। वैसे देखा जाये तो लोकतंत्र में नंबरगेम ही मायने रखता है लेकिन मोदी के लिए इसका खास महत्व नहीं है। इस बात को हम गुजरात के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भाजपा ने 2002 में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी उसके बाद पार्टी अगले चुनाव में 117 सीटों पर और उसके बाद 116 सीटों पर पहुँच गयी थी। यही नहीं, मोदी के दिल्ली आने के बाद गुजरात में जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा 99 सीटों पर आ गयी थी लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने गुजरात में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये थे। नंबरगेम ऊपर नीचे होता रहा लेकिन मोदी ने गुजरात के विकास को जरा भी प्रभावित नहीं होने दिया।

बहरहाल, देखा जाये तो लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले तक माना जाता था कि देश में मोदी के बराबर का कोई नेता नहीं है लेकिन

अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं

ललित गर्ग

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन ने ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कर्लकित किया था।

अठारहवीं लोकसभा चुनाव के नतीजे भले ही अपने अंदर कई संदेशों को समेटे हुए हैं, भले ही भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, भले ही इंडिया गठबंधन एक चुनौती के रूप में खड़ा हुआ हो, फिर भी तीसरी बार नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हुए नये भारत एवं सशक्त भारत को निर्मित करने के लिये वे पहले दो कार्यकाल से अधिक शक्ति, संकल्प एवं जिजीविषा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सीटों के लिहाज से भाजपा को भले ही नुकसान हुआ, लेकिन लगातार तीसरी बार वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ओडिशा और तेलंगाना में पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंकाया है। ओडिशा में लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी पार्टी ने बीजू जनता दल का 24 साल से चला आ रहा वचन तोड़ा। अरुणाचल प्रदेश की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव में 54 प्रतिशत मत और 46 सीटों के प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अन्तुटे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन

ने ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगाकर देश एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कर्लकित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम ने न केवल इस प्रकार के भ्रामक, गुमराह करने वाली बातों एवं मिथकों को तोड़ दिया, बल्कि इसने भारत के जीवंत, बहुलतावादी, पंथनिरपेक्षी और स्वस्थ लोकतांत्रिक छवि को पुनर्स्थापित किया है। प्रधानमंत्री मोदी का अंधविरोध करने वाला भाव-जिहादी-सम्प्रदायवादी राजनीतिक समूह अपने इस वाहियात प्रलाप एवं राष्ट्र-विरोधी परिणाम अनेक देशों में संतोषजनक रहे हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के लिये चुनाव परिणाम अनेक देशों में संतोषजनक रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह चुनाव नये जीवन का वाहक बना है। वैसे भी एक आदर्श लोकतंत्र के लिये सशक्त विपक्ष का होना जरूरी है, यही लोकतंत्र को खूबसूरती देता है। भारतीय मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को विपक्षी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने का संदेश दिया है।

इस बार के चुनाव परिणाम अनेक राजनीतिक दलों के सामने भी अनेक प्रश्न खड़े किये हैं। कौन जेल में रहेगा, इसका फैसला अदालतें करती हैं। परंतु दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव को अपने जेल के अंदर रहने या बाहर रहने का अधिकार मतदाताओं को सौंपा था, जिसका नतीजा यह प्रचंड बहुमत के बल पर भाजपा सरकार बनाने में सफल हुई है। वहीं, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भाजपा के गढ़ बने हुए हैं, जबकि देश की राजनीति में अब भी मोदी सबसे बड़े एवं वर्चस्वी नेता हैं। वे अब भी अपने चौंकाने वाले एवं आश्चर्य में डालने वाले विलक्षण एवं अन्तुटे फैसलों से राष्ट्र को विकास की नई उड़ान देते रहेंगे। भाजपा को कम सीटें मिले कारणों की समीक्षा एवं मंथन करते हुए अपनी हार के कारणों को सहजता एवं उदारता से स्वीकारना चाहिए एवं जिन गलतियों के कारण कम सीटें मिली, उन्हें दूर करना चाहिए।

इस बार के चुनाव को नियोजित एवं प्रभावी तरीके से सम्पन्न करने में चुनाव आयोग की भूमिका सराहनीय रही। भले ही इंडिया गठबंधन

के पहले भाजपा मुख्यालय में दिये उद्घोषण एवं गठबंधन दलों के साथ हुई बैठक में इन सवालियों के जवाब काफी हद तक मिल गये, जिससे शेरव बाजार ने भी तेजी पकड़ी है एवं भाजपा एवं सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। देश एक बार फिर गठबंधन सरकारों के युग में प्रवेश कर रहा है। अब यह एक हकीकत है कि मौजूदा जनादेश के मद्देनजर गठबंधन सरकार बनाना भाजपा की मजबूरी हो गई है। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने और अल्पमत में सहयोगी दलों के साथ सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सवाल उठाना जा रहा है कि पूर्ण बहुमत वाले दो कार्यकालों में देशहित के बड़े फैसले लेने वाली भाजपा क्या गठबंधन के सहयोगियों के दबाव के बीच शासन करने में खुद को सहज महसूस कर सकेगी? लेकिन मोदी के नेतृत्व में सरकार मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी और अपने संकल्पों एवं योजनाओं को आकार देगी, इसमें कोई संदेह नजर नहीं आती। देश में केंद्रीय स्तर 2009 के बाद पहली बार गठबंधन सरकार बनने जा रही है। अतीत में नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकारों का कुशलता से संचालन भी किया है और आवश्यक सुधारों को भी आगे बढ़ाया है। मनमोहन सिंह ने भी दस वर्ष तक गठबंधन सरकार का संचालन किया है, लेकिन इसकी अन्तदृष्टि नहीं की जा सकती कि उन्हें किस तरह कई बार सहयोगी दलों के अनुचित दबाव में झुकना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन सरकार की चुनौतियों से जूझते रहे। लेकिन मोदी की स्थितियाँ भिन्न हैं, वे राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, अमित शाह राजनीतिक जोड़ तोड़ के खिलाड़ी हैं, इसे देखते हुए भाजपा और उसके नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार सफलतापूर्वक अपना काम कर सकेगी, ऐसा विश्वास है। न केवल सरकार बल्कि भाजपा के बड़े मुद्दों का भी क्रियान्वयन होगा। जब-जब भाजपा के सामने अनुचित राजनीतिक दबाव की स्थितियाँ बनेंगी, सरकार कोई सार्थक रास्ता निकाल लेगी।

देकर मंजिल पर समय से पहले पहुँचने वाले नेता हैं यह बात सबको याद रखनी चाहिए।

-नौरज कुमार दुबे

स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान फिर आई नजर, ADAS 2.0 के साथ मिल सकते हैं ये सेफ्टी फीचर्स

परिवहन विशेष न्यूज

आगामी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को भारतीय सड़कों पर हैवी कैमोफ्लैग के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेक कार निर्माता अपने अपडेटेड स्लाविया और कुशाक में ADAS 2.0 पेश कर सकता है। हुड के तहत अपडेटेड स्कोडा स्लाविया में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन से पावर मिलती रहेगी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। आगामी स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट को भारतीय सड़कों पर हैवी कैमोफ्लैग के साथ टेस्टिंग के

दौरान देखा गया है। इसमें संभवतः लेवल-2 एडवांस फीचर और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। स्कोडा ऑटो इंडिया 2024 के मध्य में स्लाविया सेडान के फेसलिफ्ट संस्करण को पेश करने के लिए काम कर रही है। आइए, इसके बारे में जान लेते हैं।

डिजाइन अपडेट
आगामी सेडान के नवीनतम स्पाई शॉट्स से कुछ प्रमुख बाहरी विवरण सामने आए हैं। जासूसी तस्वीरों के अनुसार, 2024 स्लाविया का सिल्वर-मौजूदा-जनरेशन स्लाविया के समान दिखाई देता है। डिजाइन के मामले में इस मिड-साइज सेडान को एलईडी हेडलैंप का एक नया सेट, अपडेटेड ग्रिल डिजाइन, हैलोजन फ्रंट लैंप, अपडेटेड फ्रंट बम्पर और बूमरैंग के आकार का एलईडी डीआरएल मिलने की उम्मीद है।

साथ ही इसे ब्लैक कलर के मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील, शार्क-फिन एंटीना और एक स्नरूप दिया गया। MQB-A0 (IN) प्लेटफॉर्म पर आधारित 2024 Skoda Slavia में C-आकार के LED टेल-लैंप और नए डिजाइन वाले रिपर

बंपर दिए गए हैं।

सेफ्टी फीचर्स
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेक कार निर्माता अपने अपडेटेड स्लाविया और कुशाक में ADAS 2.0 पेश कर सकता है। स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट के सेफ्टी सूट में 360-डिग्री पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक से लैस होने की उम्मीद है।

इंजन और परफॉरमेंस
हुड के तहत अपडेटेड स्कोडा स्लाविया में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन से पावर मिलती रहेगी। इसका 1.0 लीटर इंजन 114 bhp की अधिकतम पावर और 178 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है, जबकि दूसरा 148 bhp की अधिकतम पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। 1.0-लीटर इंजन को 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन या AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, जबकि 1.5-लीटर इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 7-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ आता है।



कावासाकी ने ग्लोबल स्तर पर पेश की निंजा ZX6r, जानें क्या है खासियत और भारत में कब होगी लॉन्च



परिवहन विशेष न्यूज

जापानी दो पहिया वाहन निर्माता Kawasaki की ओर से हाल में ही ग्लोबल बाजार के लिए 600 सीसी की दमदार बाइक Ninja ZX6r के 2025 वर्जन को पेश किया गया है। कंपनी की ओर से पेश की गई इस सुपर बाइक में किस तरह के फीचर्स को दिया जा रहा है। कितना दमदार इंजन इसमें मिलता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। सुपर बाइक बनाने वाली जापानी कंपनी कावासाकी की ओर से 600 सीसी सेगमेंट की अपनी बाइक Ninja ZX6r के 2025 वर्जन को ग्लोबली पेश कर दिया गया है। इस वर्जन में किस तरह की खूबियों को दिया गया है। इसमें कितना दमदार इंजन मिलता है और इसे भारत में कब तक लाया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

पेश हुई Kawasaki Ninja ZX6r 2025
कावासाकी ने ग्लोबल बाजार में अपनी 600 सीसी सेगमेंट की बाइक ZX6r के 2025 वर्जन को पेश कर दिया है। इसमें कितना दमदार इंजन इस बाइक के 2025 वर्जन में सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और बाइक को पल

रोबोटिक वाइट के साथ मेटालिक ग्रेफाइट ग्रे के अलावा मेटालिक मैट डार्क ग्रे के साथ एबोनी रंग में पेश किया गया है। इसके अलावा इसमें किसी अन्य तरह का बदलाव नहीं किया गया है।

कितना दमदार इंजन
कंपनी की ओर से इस बाइक में 636 सीसी का इनलाइन फोर सिलेंडर इंजन दिया जाता है। जिससे इसे 122.03 बीएचपी की पावर और 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। बाइक को छह स्पीड गियरबॉक्स के साथ ऑफर किया जाता है। इसके अलावा इसमें 17 इंच के पहिए और 17 लीटर का पेट्रोल टैंक दिया जाता है।

कैसे है फीचर्स
बाइक में अडिस्ट और स्लिपर क्लच, राइडिंग के लिए चार मोड्स, दो पावर मोड,

ट्रेनशन लेवल के तीन स्तर, अपशिफ्ट के लिए क्लच रिफ्लैक्टर, एबीएस, ब्ल्यूटूथ कनेक्टिविटी, एलईडी लाइट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्यूल डिस्क ब्रेक, मोनोशॉक सस्पेंशन जैसे कई फीचर्स को दिया गया है।

कब आएगी भारत
फिलहाल कंपनी ने इस बाइक को ग्लोबल स्तर पर पेश किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले साल तक इसे भारतीय बाजार में भी लाया जा सकता है। इंटरनेशनल बाजार में इस बाइक की कीमत 9.51 लाख रुपये से शुरू होती है और इसके एबीएस वर्जन की कीमत 10.35 लाख रुपये तक जाती है। फिलहाल भारत में इसके 2024 वर्जन को ऑफर किया जाता है, जिसकी एक्स शुरुआत कीमत 11.20 लाख रुपये है।

स्कोडा दे रही 11.99 लाख की गाड़ी पर 2.5 लाख रुपये की बचत का मौका....



चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता स्कोडा की ओर से भारतीय बाजार में कुछ बेहतरीन कारों और एसयूवी को ऑफर किया जाता है। June 2024 में कंपनी की ओर से अपनी कार और एसयूवी खरीदने पर लाखों रुपये के डिस्काउंट ऑफर्स को दिया जा रहा है। Skoda Auto India की ओर से अपनी किस कार और एसयूवी पर इस महीने में कितना डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। चेक रिपब्लिक की वाहन निर्माता कंपनी की ओर से June 2024 में अपनी एक सेडान और एक एसयूवी पर बेहतरीन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस महीने कंपनी की किन दो गाड़ियों को खरीदने पर लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

June 2024 में मिल रहा तगड़ा डिस्काउंट
स्कोडा की ओर से June महीने में अपनी कारों पर काफी बेहतरीन ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से अपनी एक सेडान कार और एक एसयूवी पर इस महीने लाखों रुपये की बचत की जा सकती है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस महीने में अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक स्कोडा की कारों पर

बचाए जा सकते हैं।

Skoda Slavia
स्कोडा की ओर से मिड साइज सेडान सेगमेंट में Slavia को ऑफर किया जाता है। इस कार को June 2024 में खरीदने पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये बचाए जा सकते हैं। इसपर कंपनी स्पेशल बेंचिफिट के तौर पर 1.5 लाख रुपये, तीन साल का स्टैंडर्ड मेंटेनेंस पैकेज और पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी को ऑफर कर रही है। बाजार में इसकी एक्स शुरुआत कीमत की शुरुआत 11.63 लाख रुपये से हो जाती है।

Skoda Kushaq
स्कोडा की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में Kushaq को ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी को June 2024 में खरीदने पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। कंपनी की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी को खरीदने पर अधिकतम 2.5 लाख रुपये की बचत की जा सकती है। इस महीने में Kushaq एसयूवी पर स्पेशल बेंचिफिट के तौर पर 2.5 लाख रुपये, तीन साल का स्टैंडर्ड मेंटेनेंस पैकेज और पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी को ऑफर कर रही है। बाजार में इसकी एक्स शुरुआत कीमत की शुरुआत 11.99 लाख रुपये से हो जाती है।

इन पर नहीं मिलेगा ऑफर
कंपनी की ओर से इस महीने में फुल साइज एसयूवी कोडियाक और लगजरी सेडान कार सुपबं पर किसी भी तरह का कोई ऑफर या डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।

मारुति एरीना की किस गाड़ी पर जून 2024 में मिल रहा कितना डिस् काउंट, जानें डिटेल

देश की सबसे ज्यादा कारों की बिक्री करने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की ओर से June 2024 में एरीना डीलरशिप पर उपलब्ध कारों पर हजारों रुपये के डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से किस कार को खरीदने पर कितना कैश डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस और कॉर्पोरेट बोनस के तौर पर डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। June 2024 में अगर आप कार खरीदने का मन बना रहे हैं, तो मारुति सुजुकी एरीना की कई कारों पर कंपनी की ओर से डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनी की ओर से किस कार पर कितना डिस्काउंट कंपनी की ओर से ऑफर किया जा रहा है। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

ऑल्टो के 10
मारुति की ओर से ऑल्टो के 10 पर June 2024 में अधिकतम 63100 रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। कंपनी

ऑल्टो के 10 पर 45 हजार रुपये का कन्स्यूमर ऑफर, 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और अतिरिक्त बेंचिफिट के तौर पर 3100 रुपये के ऑफर दे रही है।

एस प्रेंसो
मारुति की एस प्रेंसो कार पर भी June 2024 में अधिकतम 58100 रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। June महीने में इसके एजीएस वेरिएंट पर सबसे ज्यादा छूट दी जा रही है। इसके अलावा एस प्रेंसो के सीएनजी और मैनुअल वेरिएंट्स पर 53100 रुपये के डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है।

सेलेरियो
सेलेरियो पर मारुति June महीने में अधिकतम 58100 रुपये के ऑफर दिए जा रहे हैं। सेलेरियो पर June महीने में 40 हजार रुपये के कन्स्यूमर ऑफर के साथ ही इस गाड़ी पर 15 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 3100 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट का फायदा मिल रहा है।

वैगन आर
कंपनी की ओर से वैगन आर पर भी अधिकतम 63500 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। वैगन आर पर भी सेलेरियो की तरह ही June महीने में 40 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है।

स्विफ्ट
कंपनी की स्विफ्ट कार को युवाओं के बीच काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इस कार की तीसरी जेनरेशन वाले एजीएस वेरिएंट पर June महीने में 43100 रुपये तक बचाए जा सकते हैं। वहीं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट्स पर 38100 रुपये और सीएनजी वेरिएंट्स पर June महीने में 18100 रुपये का फायदा मिल रहा है। इसके नए जेनरेशन वेरिएंट पर इस महीने में किसी भी तरह का डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है।

डिजायर
मारुति की ओर से डिजायर कार पर भी June 2024 में अधिकतम 30 हजार रुपये के ऑफर मिल रहे हैं।

ब्रेजा
मारुति की ब्रेजा पर भी June 2024 में डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी की ओर से इस एसयूवी पर इस महीने में अधिकतम 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है।

ईको
मारुति की ओर से सात सीटों के विकल्प के साथ आने वाली ईको पर भी इस महीने में छूट दी जा रही है। इस कार पर इस महीने में 33100 रुपये और सीएनजी वेरिएंट पर 20 हजार रुपये का फायदा उठाया जा सकता है।



जल संकट से जूझता प्रदेश



अनुज आचार्य

वल्ड बैंक ने तो पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए स्वच्छ पानी को व्यर्थ बहाने वालों से टैक्स तक वसूलने की अनुशंसा भी की है और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं आबंटन की सलाह दी है।

जल शक्ति विभाग ने शिकायतों के निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर 18001808009 भी जारी किया हुआ है। लेकिन शिकायत मिलाने के बाद भी शिकायतकर्ता दुखी रहता है तो फिर ऐसे प्रयास भी औचित्यहीन ही माने जाएंगे। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री मेहनती लीडर हैं, आम पब्लिक की सुनते भी हैं, लेकिन जब तक अधिकारी फील्ड में नहीं उतरेंगे, तब तक अच्छे रिजल्ट आने की संभावना कम ही है।



हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा की मनोरम धौलाधार पर्वत श्रेणी तले बसने वाले मेरे जैसे अनेकों लोगों ने पिछले 50 वर्षों में काफी कुछ बदलते देखा है। औद्योगिक विकास की बात को छोड़ भी दें तो पुराने मकानों की जगह कंक्रीट के जंगल उभर आए हैं और जहां पहले कभी फसलें लहलहाती थीं, वहां केवल अब सीमेंट और सरिए के पक्के मकानों की बहुतायत हो गई है और फसलें चौपट हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में साल दर साल स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजनाओं में बढ़ोतरी के बावजूद आज प्रदेश के कई हिस्सों में जल संकट गहराया हुआ है, तो इससे निबटने के लिए सरकार को युद्धस्तर पर राहत के उपाय ढूंढने ही पड़ेंगे। विभाग के अनुसार प्रदेश में कुल 10067 पेयजल परियोजनाएं हैं। इनमें ज्यादातर में जलस्तर घट गया है, वहीं 350 पेयजल परियोजनाएं ऐसी हैं जो लगातार सूख रही हैं। इसके लिए अधिकतर नागरिकों के घरों में वर्षाजल संग्रहण टैंकों का निर्माण करवाना होगा, लेकिन कई पंचायत प्रधान वर्षा जल संग्रहण टैंकों के निर्माण में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इस लेख के लेखक को भी सरकार द्वारा दो बार वर्षा जल संग्रहण टैंक स्वीकृत किया गया, लेकिन उपमंडल बैजनाथ की खडानाल पंचायत द्वारा टैंक का निर्माण करवाया ही नहीं गया। क्या कभी इस प्रकार का नकारात्मक रवैया रखने वाले जनप्रतिनिधियों पर कोई अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई भी होगी और लाभार्थी को कोई लाभ मिलेगा? पंचायतों द्वारा स्वीकृत वर्षा जल संग्रहण टैंकों, लेकिन पोंडिंग

अथवा अधूरे छोड़े गए और जिनके निर्माण में अनियमितता बरती गई हो, ऐसे मामलों में संबंधित पंचायत प्रतिनिधियों एवं खंड विकास अधिकारियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। वल्ड बैंक ने तो पेयजल की बर्बादी रोकने के लिए स्वच्छ पानी को व्यर्थ बहाने वालों से टैक्स तक वसूलने की अनुशंसा भी की है और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन एवं आबंटन की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों का सीजन कोई ज्यादा लंबा नहीं चलता है, लेकिन यह दो महीने जल शक्ति विभाग के लिए कड़ी परीक्षा वाले होते हैं। जहां कुशल, योग्य और हजरत अधिकारी होते हैं, वहां से पेयजल संकट को लेकर कम शिकायतें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जहां कुछ क्षेत्रों के अफसर अनियमित पेयजल की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते हैं और फील्ड में जाने की जहमत भी नहीं उठाते हैं। वहां के निवासियों को कई दिनों तक व्यवस्था में सुधार होने का इंतजार करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग द्वारा घोषित लक्ष्यों में पहले स्थान पर पेयजल आपूर्ति योजनाओं द्वारा प्रदेशवासियों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना ही रखा गया है। 15 मई 2023 तक प्रदेश में 41835 हैंडपंप लगाए जा चुके थे। वर्तमान समय में जिस प्रकार से जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और नित नई कालोनियां विकसित हो रही हैं अथवा गांव के भीतर नए पेयजल कनेक्शन की मांग बढ़ रही है,

उसके हिसाब से पुरानी जलापूर्ति लाइनों में कोई सुधार न होने और पुरानी पाइपों से ही पेयजल आपूर्ति की वजह से लोगों को अपर्याप्त पेयजलापूर्ति हो रही है और गर्मियों के इस सीजन में हालात और भी गंभीर और खराब हैं। सरकार की मंशा तो ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने की होती है, लेकिन चंद अधिकारियों की सुस्त कार्यशैली के चलते फजीहत भी सरकार की ही होती है। यह सही है कि विभाग के ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी पिछले दिनों चुनाव झूट्टी पर थे। ऐसे में उच्च अधिकारियों को पहले से योजना बनाकर जल संकट का हल निकाल लेना चाहिए था। हमें यह भी देखना होगा कि पारंपरिक जल स्रोतों में जल संकुचन, अनियमित पेयजल आपूर्ति, गिरते भूजल जल स्तर, फील्ड स्टाफ की कमी और पानी की खराब गुणवत्ता के चलते हिमाचल के कई हिस्सों में शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति दोनों की स्थिरता में खतरा पैदा कर दिया है और पेयजल को लेकर अब तो दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों से भी संघर्ष की खबरें अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। लाख टके का सवाल है कि करोड़ों की पेयजल योजनाएं बिना मानव श्रम शक्ति के किस प्रकार से अपनी उपयोगिता साबित कर पाएंगी? अब आप 15 मई 2023 की विभागीय मानव श्रम शक्ति का विश्लेषण देखें तो जलशक्ति विभाग के विभिन्न 49 श्रेणियों के लिए स्वीकृत 4173 पदों में से 2586 पद भर हुए हैं और 1587 पद रिक्त चल रहे हैं। इसलिए विभाग में नई नौकरियों का सृजन जल्द हो, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जल शक्ति विभाग का नारा 'सेव वाटर सेव लाइफ' तभी सार्थक होगा जब लोगों को नियमित पेयजल आपूर्ति संभव होगी। जल शक्ति विभाग ने शिकायतों के निवारण के लिए एक टोल फ्री नंबर 18001808009 भी जारी किया हुआ है। लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी शिकायतकर्ता दुखी रहता है तो फिर ऐसे प्रयास भी औचित्यहीन ही माने जाएंगे। जल शक्ति मंत्री मुकेश अग्निहोत्री मेहनती लीडर हैं, आम पब्लिक की सुनते भी हैं, लेकिन नए जल संकट के आला अधिकारी अपना कुर्सी मोह छोड़कर फील्ड में उतर कर पसीना नहीं बहाएंगे, तब तक अच्छे रिजल्ट आने की संभावना कम ही है। हिमाचल से बाहर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भी गंभीर जल संकट का सामना कर रही है, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक दुनिया की चौदह फीसदी आबादी के सामने जल संकट खड़ा हो जाएगा। यह समय की मांग है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती आबादी के कारण पेयजल की मांग में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत नवीन योजनाओं पर युद्धस्तर पर काम होना चाहिए। आम नागरिक को पहले 'हर घर जल' तो मिले, तभी वह 'सेव वाटर सेव लाइफ' के नारे पर अमल करेगा। इस समस्या का तुरंत समाधान खोजना होगा।

संपादक की कलम से गठबंधन सहारे मोदी सरकार

नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। भाजपा न केवल लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है, बल्कि 291 सांसदों वाले एनडीए का सदन में स्पष्ट बहुमत भी है। बहुमत का जादूई आंकड़ा 272 है। नियम और परंपरा के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले भाजपा-एनडीए के नेता मोदी को, सरकार बनाने के लिए, आमंत्रित करेंगे। भाजपा और मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हैं। यह भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने घोषित भी किया है, लेकिन इस बार मोदी एक 'मिथक' और निरंकुश भाव से काम करने वाले नेता साबित नहीं हो सकेंगे। चूँकि जनदेश कमजोर और गठबंधन का है, लिहाजा इस बार तेलुगू दम पार्टी (टीडीपी) और जनता दल-यू.सी.ई.स. सहयोगियों की सलाह और पूछ भी अनिवार्य होगी। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबु नायडू केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकारों और भाजपा की वाजपेयी सरकार के दौरान संयोजक और सहयोगी रह चुके हैं। वह बार-बार सरकारों को बाध्य करते थे और अपनी मांगें मनवाने की जिद करते थे। अंततः उन्होंने एनडीए छोड़ कर फौजदार बन गए। बेशक उस दौर की तुलना में अब भाजपा सांसदों की संख्या काफी है, लेकिन स्पष्ट बहुमत से 30 सांसद कम हैं। लिहाजा सहयोगी दलों के समर्थन के बिना मोदी सरकार भी अस्थिर रहेगी। यह जनदेश 2014 और 2019 से बिल्कुल भिन्न है। प्रधानमंत्री मोदी 10 साला कार्यकाल के दौरान लगभग निरंकुश होकर फैसले लेते रहे। प्रधानमंत्री देवेंद्र फौलदार की उसी तर्ज पर काम करता रहा। अब यह गठबंधन की सरकार होगी, लिहाजा प्रधानमंत्री को समान नागरिक संहिता, एक देश एक चुनाव, कुछ आर्थिक सुधार, एनएसआर सरीखे मुद्दों पर फिलहाल विराम लगाना पड़ेगा अथवा टीडीपी और जद-यू की सहमति सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। इस बार विपक्ष भी ताकतवर होगा। उनका नेता प्रतिपक्ष भी होगा, लिहाजा मुद्दों और विधेयकों पर विपक्ष की सहमति को भी टाला नहीं जा सकेगा। इस बार मोदी सरकार के लिए कोई भी संविधान संशोधन बिल पारित कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुमत नहीं है। कांग्रेस के 99 और सपा के 37 सांसद चुनकर लोकसभा में आ रहे हैं। 'इंडिया' की कुल ताकत पर्याप्त है। पीएमओ पर भी गठबंधन के सहयोगियों की 'निगाह' बराबर बनी रहेगी। फिलहाल नायडू और नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर समर्थन और गठबंधन की गारंटी दी है, लेकिन उन दोनों के अतीत का इतिहास संदिग्ध रहा है। उससे उन्होंने सबक भी सीखा होगा! दोनों दल लोकसभा में स्वीकार का पद चाहते हैं। वाजपेयी सरकार के दौरान टीडीपी के बालयोगी स्पीकर होते थे। बहरहाल अभी तो मोदी सरकार को शपथ ग्रहण करनी है। इस बार 23.43 करोड़ मतदाताओं ने मोदी के नेतृत्व को वोट दिए हैं। यकीनन यह विश्व कीर्तिमान है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के नाम इतने वोट नहीं डाले गए। फिर भी भाजपा को आत्ममंथन करना है कि जनदेश की दशा और दिशा एकदम कैसे बदल गई? वाराणसी सीट पर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी 4 लाख से अधिक वोट से जीते थे, लेकिन इस बार यह फासला 1.5 लाख ही रह गया। ये वोट कम क्यों हुए? क्या दलित, ओबीसी, युवा मतदाता भाजपा से विमुख हुए हैं, लिहाजा समीकरण पलट गए हैं? ऐसे विश्लेषण सामने आए हैं कि ओबीसी, दलित, मुसलमान के अतिरिक्त वोट सपा और कांग्रेस के पक्ष में गए, नतीजतन उग्र के तमाम समीकरण पलट गए और भाजपा पराजित-सी हो गई। बसपा को मात्र 9 फीसदी वोट मिले और वह एक भी सीट जीत नहीं पाई, इससे भी सपा और कांग्रेस को फायदा हुआ। अयोध्या का राम मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं बन सका, एक देश एक चुनाव का भरोसा अब भी 'दीदी' पर ही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की 'शिवसेना' और अजित पवार की एनडीए भाजपा पर वोट ही साबित हुई, लिहाजा नुकसान भाजपा को ही हुआ।

राय छोटा हिमाचल, सबक बड़े-2

आश्चर्य यह कि जनता की अदालत हर बार सत्ता की मदहोशी में हार जाती है और फिर जब अपना ही नेतृत्व शहंशाह बनता है तो मतदान की लाठी उठ जाती है। हिमाचल में मतदान की लाठियां चारों ओर पड़ी हैं। कोई इसे कबूल करे या न करे, लेकिन हकीकत में हर पार्टी कहीं तो हारी और पार्टियों के नेता या सियासी ताकत को भी हारना पड़ा। हारना पड़ा उस संबोधन को जिसके बलबूते चुनाव की चिमनियां जलीं थीं। हारना पड़ा उस दम को जो सामने खड़े विरोध को जमीन पर सुलाना चाहता था। कहीं भितरघात को मात देकर चुनाव खिलखिलाया, तो कहीं आरोपों की होली जला कर वही मुकराया। जाहिर तौर पर चुनाव ने कई नेताओं के वर्तमान को प्रश्नों की फांस पर टांग कर पूछा है, तेरा क्या होगा कालिया, तो कहीं जिम्दार का मौका भी दिया है। कुछ सबक पार्टी स्तर पर कांफ्रेंस और भाजपा को बांट लेने चाहिए, तो कुछ के आधार पर सीमा रेखा खींच लेनी चाहिए। लोकसभा की चार सीटें गंवा कर कांग्रेस को भाजपा का संगठनात्मक हनुन देना चाहिए। उनके वक्त्र का संयम देना चाहिए जिन्होंने उप तफक नहीं की और कांग्रेस से छिटके नेता अपना लिए। अपनी अदला बदली में कांग्रेस ने भले ही दो विधायक एवं मंत्री जीत दिए, लेकिन लोकसभा के परिदृश्य में ये नेता बौने हो गए या सरकार के कारनामों से छिटे पड़ गए। क्यों ओपीएस की घंटी इस चुनाव में नहीं बजी और महिलाओं के लिए निर्धारित पंद्रह सौ की राशि थोड़ी पड़ गई। कांग्रेस का घोषणापत्र क्यों हिमाचल सरकार की गारंटियों से पिछ कर चकनाचूर हुआ। जनता ने अपनी तरह के अविश्वास में भाजपा और कांग्रेस के लिए कठघरे तैयार किए। उसे यह मंजूर न था कि सरकार के गठन में बरिष्ठ नेताओं के पतन का जतन हो। जनता विधायकों को लोकसभा की उम्मीदवारों में स्वीकार नहीं कर पाई, लिहाजा लौटा दिए विक्रमादित्य सिंह और विनोद सुल्तानपुरी उसी विधानसभा में। जनता ने राज्य सरकार के आंकड़े पूरे किए और केंद्र सरकार में भी आंकड़े दिए। इसीलिए जनता को स्वीकार करो। कब तक सत्ता की सोदीबाजी में कर्मचारियों के त्योहार में सरकार को भाजपा अस्थिर करने के ताकत होती, तो कंगना क्यों जीतती या आनंद शर्मा क्यों हारते। मतदाता अत किस्ती गारंटी का गुलाम नहीं, इसलिए सुखू जी राज्य की वित्तीय सेहत को ठीक करेंगे तो बदले में जनता खुश होगी। दूसरी ओर चुनी हुई सरकार को भाजपा अस्थिर करने की कोशिश करेगी, तो जनता दीवार बन कर खड़ी होगी। सुखू सरकार को अपने मंत्रियों की छवि व जनता के बीच स्वीकारोक्ति का मूल्यांकन करना होगा। अधिकांश मंत्रियों और कैबिनेट रैंक के कार्ड होल्डर की लुटिया डूबी है, तो यह मंत्रिमंडल और सरकार के पदों के आबंटन पर पुनर्विचार की मांग भी है। आश्चर्य यह कि कांगड़ा में सरकार का असंतुलन और उसकी भरपाई में बंटे पद अब चुनाव परिणामों के घाव की पीड़ा के पात्र बन रहे हैं। सरकार को अपना दौर, धरौं और अदब बदलना पड़ेगा और यह भी कि प्रशासनिक मशीनरी में सुराभान के लिए बदलाव चाहिए। कई जिलाधीश, जिलों के पुलिस कप्तान, सचिव और विभागीय अध्यक्ष बदल कर काम पर जोर देना होगा। असली हिमाचल सचिवालय में नहीं फील्ड में किसी छोटी सी शिकायत के साथ खड़ा होता है, इसलिए उन रिवायतों का पुनर्जीवित करना होगा जो अतीत में सरकार को शीतकालीन प्रवास के माध्यम से नीचे लाती थीं और इमशला में सचिवालय में मंत्री बैठा करते थे। मंडी से विक्रमादित्य सिंह का हारना उनके परिवार, वीरभद्र सिंह की विरासत और सत्ता के संघर्ष के लिए सबक लेकर आ रहा है। वहां प्रतिभा सिंह से संसदीय पद का खोना इसलिए भी सबक दे रहा है क्योंकि वह प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष होने के नाते संगठन की शक्ति का प्रतीक थीं।

लगता है तेजी से बदलते इस युग में हमें प्रेम को नए अर्थ देने पड़ेंगे। बहुत दिन तक शरीर से शरीर के मिलन और गम सांसों की अदला-बदली को हम प्रेम का सुनहरा प्रेम देते रहे। कवि कर्म को प्रेमिल तितलियों के बहुरंगे पंखों के साथ बांधते रहे। लेकिन फिर जब जीवन के तराजू पर ये रंग-बिरंगे पंख टूट कर तुलने लगे, तो इसमें सूफ्री काव्य से लेकर छायावाद और रहस्यवाद की ओट लेने का प्रयास भी किया गया। लेकिन आज प्रेम कैसा बेहाल हुआ जाता है। नारी स्वातंत्र्य और सशक्तिकरण के इस डिक्को रूप में घूंघट ओढ़ कर बेठा प्रेम का यह सकुचाता रूप घूंघट ओढ़ बैठा नजर आता है। एक और रोपेल विमान को उड़ाने के लिए महिला पायलट सामने आ रही हैं और दूसरी ओर दिल्ली के निर्भया कांड

विचार

परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संयमित जीवनशैली अपनाकर व्यक्ति आध्यात्मिकता की सीढ़ियां चढ़ता रह सकता है और अंततः जीवन से सीखने की जिस आवश्यकता के कारण उसने जन्म लिया था, उसे पूरा करते हुए एक-एक बाधा पार करते हुए, हम जीवन का वह लक्ष्य पा सकते हैं जिसे हर धर्म नैतिक-नैतिक कहकर पुकारता है। हम ज्योतिपुंज तो हैं ही, पर हमने खुद पर ढक्कन लगा रखा है, वह ढक्कन हट जाए तो सब कुछ खुद-ब-खुद संभव होता चलता है। इस प्रकार हम वासना के अनुभव से आगे बढ़कर उपासना के आनंद में लीन होना सीख लेते हैं। वासना से उपासना की यह यात्रा ही अंततः हमारी मुक्ति का साधन है। यह सच है कि पैदा होना, बड़े होना, बूढ़े होना और मर जाना हमारी नियति है। सभी जीवित प्राणियों में नर और मादा के मिलन से नई पीढ़ी का जन्म होता है। इसे बनाए रखने के लिए प्रकृति ने नर और मादा में पारस्परिक आकर्षण पैदा किया और यह भी सुनिश्चित किया कि दोनों एक-दूसरे के बिना खुद को अधूरा महसूस करें। जब प्रकृति का प्रवधान ऐसा है कि नर और मादा एक-दूसरे पर निर्भर हैं तो यह सोचना बेमानी है कि जीवन में वासना नहीं होगी। वासना के कई रूप हैं। इच्छाएं, लालसाएं, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, डर, उदासी, पछतावा आदि भावनाएं वासना का ही रूप हैं, परंतु वासना का सर्वाधिक मुखर रूप नर और मादा का मिलन है, सहवास है। पशु-पक्षियों में नर और मादा के मिलन का समय नियत है।

और हिमाचल के गुडिया कांड की पुनरावृत्ति हाथरस और बलरामपुर कांड जैसे निर्मम दुष्कर्म कांडों में हो रही है, जिनमें जाति और धर्म का कटघरावादी राजनीतिकरण चुनाव लड़ने और वोट हथियाने का साधन बन रहा है। लीजिए, वक्त बदलने के साथ-साथ प्रेम करने के पैमाने भी बदल गए। अब 'सजनी वही जो पिया काव्य से लेकर छायावाद और रहस्यवाद वही जो खोजी को नेता बनाए। चुनाव जितवाए। सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचाए। सीढ़ी के शिखर तक पहुंचता व्यक्ति चिल्लाता है, 'नहीं, मैं अब और अन्याय नहीं होने दूंगा। दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा।' दूध तो वेगवादी हो ऊंची मॉजिलों तक जाएगा, और पानी झुग्गी-झोंपड़ियों में खरात की तरह बटेगा, बशर्ते कि उसमें इतना

प्रदूषण न हो जाए कि चिकित्सा विशारद उसे कोरोना फैलाने का कारण ही बताते लगे। आप कहेंगे कि ऐसा असम व्यवहार तो सदियों से होता आ रहा है। आदमी को जूता बनाने की परम्परा आज की नहीं है। नहीं तो कालं मास्स दो सदी पहले 'दास कैपिटल' क्यों लिखते? परंतु लिखने के बाद उसके लिए खोखले भाषण देने की परम्परा तो आज से मकबूल हुई। अब तो लोगों को इस प्रक्रिया से इतना इश्क हो गया लगता है कि लोग प्रेम की परिभाषा बदल बैठे। इस रीति-नीति का पालन करो तो थथेली पर सरसों उगाने की कल्पना सच होती लगती है। यही है आज का प्रेम? उसका कोई टकसाली रूप भी नहीं। वक्त बदलने के साथ इसे अपना रंग बदलते देर नहीं

लगी। लेकिन इतना ही क्यों? अकबर इलाहाबादी की सुर में कहें, तो यही कहेंगे कि हाकिम को रियाया कि बहुत फिक्र ही नहीं, बहुत इश्क है, लेकिन अपना डिनर खाने के बाद। यह डिनर दुनिया भर में अभी प्रसारित हुआ रिश्ततखोरी का सूचकांक आपको बता सकता है कि इस देश के भद्र जनों के रिश्ततखोरी, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार से इतना प्यार हो गया कि दुनिया के कम से कम छिहर देश पछले साल अगर इससे कम बेईमान थे, तो इस बरस सतह तर दर आगे आ गए। पहले बरखुरदार की शादी के लिए लडकी तलाशते हुए इशारा किया जाता था कि आमदनी तो ठीक है, ऊपर से कुछ बालाई भी हो जाती है। अब तो परिचय में बालाई आमदन का ब्यौरा पहले दिया

जाता है। असल वेतन की खबर कौन पूछता है? अब इश्क उन लोगों से ही होता है, जो जल्द से जल्द अपने आपको साइकिल से बदल कर बीएमडब्ल्यू में तबदील कर लें। शुरू से सुनते आए हैं कि प्रेम की गली अति संकरी, जिसमें दो न समाए। प्रेमी और प्रेमिका एक रूप हो जाएं। यही है असली प्रेम। जनाब प्रेम की गली तो आज भी सांकी है, लेकिन इतनी सांकी भी नहीं कि जिसमें प्रेमी और उसकी आयातिवा गाड़ी न समा सके। हां, अगर प्रेमी उग्र भर अपनी फटीचर साइकिल पर भूतपूर्व प्रेमिका अर्थात वर्तमान पत्नी के लिए अपने मैले थैले में कच्ची ढोने का भविष्य दिखाए तो भला ऐसे प्रेमी के लिए इस संकरे प्रेम मार्ग पर चलने के लिए जगह कहाँ? सुरेश सेठ

छिलकों की छाबड़ी : प्रेम के नए अर्थ

यही नहीं, पशु-पक्षियों में सहवास के लिए स्वीकृति का अधिकार मादा के पास है, यानी, मादा की सहमति के बिना सहवास संभव नहीं है। यही कारण है कि पशुओं की बहुत सी प्रजातियों में नर आपस में युद्ध करते हैं और विजता नर अपने समूह की सभी मादाओं का स्वामी बन जाता है। मजेदार बात यह है कि पशुओं की किसी भी प्रजाति में यह मुकाबला या युद्ध मादाओं में कभी नहीं होता। जो नर विजता रहता है, वह सभी मादाओं का स्वामी हो जाता है और सभी मादाएं उस नर को सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं, बिना किसी संकोच के और बिना किसी ईर्ष्या के। पशु-पक्षियों में सहवास का एक निश्चित मौसम होता है और एक सामान्य तौर से निश्चित उग्र होती है। मानव जाति पर ऐसा कोई बंधन नहीं है। एक महिला और पुरुष जब भी चाहें, जिसे भी चाहें, जिस उम्र में भी चाहें, दोनों में सहमति हो तो वे सहवास कर सकते हैं। उन पर कोई और बंधन नहीं है। मानव जाति पर सहवास के समय को लेकर, मौसम को लेकर, यहां तक कि स्वीकृति को लेकर भी कोई बंधन नहीं है। यही कारण है कि मानव जाति में छोटे बच्चों का शारीरिक शोषण और महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी दुष्प्रवृत्तियां और दुखद घटनाओं का जन्म हुआ। मानव जाति में एक और अंतर यह भी है कि मादा सिर्फ मादा ही नहीं है, महिला भी है, और तब भी है और उसका अपना दिल और दिमाग भी है। वह स्वयं भी किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो सकती है और मिलन के लिए पहल भी कर सकती है। देश, काल और समाज की रीतियों के मुताबिक किसी पुरुष को लड़कियां या प्रेमिकाएं हो सकती हैं या किसी महिला के कई पति या प्रेमी हो सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि विपरीत लिंग का आकर्षण, सहवास का सुख, परिवार में रहने से सुरक्षा का अहसास

वासना और उपासना

और परिवार बढाने की इच्छा जैसे कई कारण हैं जो मानव जाति को सहवास के लिए प्रेरित करते हैं। लम्बोलुबाव यह कि सहवास इस सृष्टि का एक अनिवार्य 'कर्म' है और इससे मुह चुराने का कोई कारण नहीं है। भारतवर्ष में एक हजार साल की लंबी गुलामी के समय महिलाओं पर हुए अत्याचार के कारण महिलाओं को पदों में रखने की प्रथा अस्तित्व में आई, लेकिन उसका दुष्परिणाम यह ही हुआ कि 'सभ्य' कहे जाने वाले समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों पर अंकुश लगा, वे आर्थिक रूप से परतंत्र हो गईं, पीढ़ी दर पीढ़ी महिलाएं और ज्यादा दब्यु हो चली गईं और अंततः वे लगभग हर मामले में पुरुषों पर निर्भर हो गईं। ऐसा सिर्फ 'सभ्य समाज' में हुआ, क्योंकि जंगलों और गुफाओं में रहने वाली, 'असभ्य' मानी जाने वाली जनजाति में महिलाएं आज भी सभ्य समाज की महिलाओं की अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र हैं। पिछली आधी शताब्दी से सभ्य कहे जाने वाले समाज में महिला अधिकारों की बात चली है, महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और उन्होंने हर क्षेत्र में

वासना और उपासना

पुरुषों से ज्यादा बढ़िया काम किया है और अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन अभी भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इस स्वाभाविक अधिकार से वंचित है। मानव समाज में महिला स्वतंत्र हो या न हो, पर विपरीत लिंग का आकर्षण ऐसा है कि सहवास जीवन का अनिवार्य अंग है। आर्थिक और तकनीकी प्रगति के साथ ही डेटिंग, बलात्कार, शादी के बाद के अवैध रिश्ते और तलाक की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। दोनों पक्ष इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि व्यक्ति भी तभी संभव है जब हर पुरुष के साथ कोई महिला है, और हर महिला के साथ कोई पुरुष है। वासना का यह खेल व्यक्ति का कारण न बने, इसके लिए 'सहज संन्यास' की परंपरा में 'दिव्य समागम' का प्रावधान है और यह सिर्फ शादीशुदा जोड़ों, विधुर पुरुषों या विधवा महिलाओं के लिए ही मान्य है। 'दिव्य समागम' एक ऐसी अजूबी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवित या मृत जीवनसाथी से सहवास का आनंद ले सकता है। 'दिव्य

समागम' की खासियत यह है कि यह कोई शारीरिक क्रिया न होने के बावजूद वैसा ही आनंद और वैसी ही संतुष्टि प्रदान करता है। यह व्यक्ति को चरित्र भ्रष्ट करने से बचाता है और यदि इसे सामाजिक स्वीकृति मिल जाए तो यह शारीरिक शोषण के सामाजिक अपराधों की रोकथाम का एक बड़ा साधन हो सकता है। 'सहज संन्यास' की परंपरा में सहवास को नकारा नहीं जाता, पर आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए संयमित व्यवहार की अनुशंसा की जाती है। अति कहीं भी अस्वीकृति होती। परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए संयमित जीवनशैली अपनाकर व्यक्ति आध्यात्मिकता की सीढ़ियां चढ़ता रह सकता है और अंततः जीवन से सीखने की जिस आवश्यकता के कारण उसने जन्म लिया था, उसे पूरा करते हुए एक-एक बाधा पार करते हुए, हम जीवन का वह लक्ष्य पा सकते हैं जिसे हर धर्म नैतिक-नैतिक कहकर पुकारता है। हम ज्योतिपुंज तो हैं ही, पर हमने खुद पर ढक्कन लगा रखा है, वह ढक्कन हट जाए तो सब कुछ खुद-ब-खुद संभव होता चलता है। इस प्रकार हम वासना के अनुभव से आगे बढ़कर उपासना के आनंद में लीन होना सीख लेते हैं। वासना से उपासना की यह यात्रा ही अंततः हमारी मुक्ति का साधन है। 'सहज संन्यास मिशन' में हम इसी की राह पर चलना सीखते और सिखाते हैं, और यहां सबका स्वागत है! स्तिरिचुल हीलर सिद्धगुरु प्रमोद जी गिन्नीज विश्व रिकार्ड विजेता लेखक

मई 2024 में भी खूब बढ़ी घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या, 14 करोड़ के करीब पहुंचा आंकड़ा

परिवहन विशेष न्यूज

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को कहा कि मई में घरेलू हवाई यात्री यातायात साल-दर-साल 5.1 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 138.9 मिलियन हो गया है। पिछले महीने एयरलाइनों की क्षमता तैनाती में साल-दर-साल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अप्रैल 2024 की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक है। एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 24 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात लगभग 154 मिलियन था।

नई दिल्ली। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने गुरुवार को कहा कि मई में घरेलू हवाई यात्री यातायात साल-दर-साल 5.1 प्रतिशत बढ़कर अनुमानित 138.9 मिलियन हो गया और यह कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक था। इक्रा ने यह भी कहा कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात में निरंतर सुधार के बीच भारतीय विमानन उद्योग का दृष्टिकोण स्थिर है, अपेक्षाकृत स्थिर लागत वातावरण और वित्त वर्ष 2025 में प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

घरेलू हवाई यात्री यातायात में इतनी बढ़ोतरी पिछले महीने एयरलाइनों की क्षमता तैनाती में साल-दर-साल 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और अप्रैल 2024 की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक है। एजेंसी के अनुसार, वित्त वर्ष 24 के लिए घरेलू हवाई यात्री यातायात लगभग 154 मिलियन था, जिसमें साल-दर-साल लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार यह वित्त वर्ष 2020 में लगभग



142 मिलियन के प्री-कोविड स्तरों को पार कर गया। रेटिंग एजेंसी ने कहा, पिछले वित्त वर्ष में भारतीय वाहकों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात लगभग 29.68 मिलियन था, जिसमें साल-दर-साल लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। एटीएफ की कीमत में हुई बढ़ोतरी इक्रा के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में औसत एटीएफ की कीमत 103,499 रुपये प्रति किलोलिटर रही, जो वित्त वर्ष 2023 में 121,013 रुपये प्रति किलोलिटर से 14 प्रतिशत कम है, लेकिन वित्त वर्ष 2020 में 65,368 रुपये प्रति किलोलिटर के प्री-कोविड स्तरों की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। एजेंसी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में औसत एटीएफ की कीमत

साल-दर-साल आधार पर 5.4 प्रतिशत अधिक रही। जून 2024 में इसमें क्रमिक रूप से 6.5 प्रतिशत की गिरावट आई। एयरलाइनों के खर्च में ईंधन की लागत का हिस्सा लगभग 30-40 प्रतिशत होता है। परिचालन व्यय का लगभग 45-60 प्रतिशत, जिसमें विमान पट्टे का भुगतान, ईंधन व्यय और विमान और इंजन रखरखाव व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है, डॉलर के संदर्भ में दर्शाया जाता है। धीरे-धीरे बढ़ेगी कमाई कुछ एयरलाइनों पर विदेशी मुद्रा ऋण है। जबकि घरेलू एयरलाइनों के पास अंतरराष्ट्रीय परिचालन से उनकी आय की सीमा तक आंशिक प्राकृतिक हेज है। कुल मिलाकर, उनके शुद्ध भुगतान विदेशी मुद्रा में हैं। एजेंसी

ने कहा कि व्यवसाय की उच्च निश्चित-लागत प्रकृति के कारण उद्योग की आय में सुधार की गति धीरे-धीरे होने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उद्योग ने एटीएफ की ऊंची कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के डिप्रिसिएट के कारण वित्त वर्ष 2023 में लगभग 170-175 बिलियन रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज किया। इक्रा को उम्मीद है कि भारतीय विमानन उद्योग वित्त वर्ष 2025 में लगभग 30-40 अरब रुपये का शुद्ध घाटा दर्ज करेगा, जैसा कि वित्त वर्ष 2024 में देखा गया था, जो वित्त वर्ष 2023 में लगभग 170-175 अरब रुपये के स्तर से काफी कम है, क्योंकि एयरलाइंस में यात्री यातायात में अच्छी वृद्धि जारी है और मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखा गया है।

पेटीएम ने ट्रेवल कार्निवल सेल का किया एलान, ट्रेन-बस बुकिंग पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; बाकू की उड़ान भी हुई सस्ती

पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए यात्रा कार्निवल सेल की शुरुआत की है। इस यात्रा कार्निवल सेल के साथ ट्रेन और बस की बुकिंग और बाकू (अजरबैजान) की फ्लाइट्स पर 25% की छूट के साथ मेगा डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। इस सेल के साथ पेटीएम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर 10%-25% तक की छूट दे रहा है।

नई दिल्ली। पेटीएम ने अपने ग्राहकों के लिए यात्रा कार्निवल सेल की शुरुआत की है। इस यात्रा कार्निवल सेल के साथ ट्रेन और बस की बुकिंग और बाकू (अजरबैजान, Azerbaijan) की फ्लाइट्स पर 25% की छूट के साथ मेगा डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर मिलेगी छूट इस सेल के साथ पेटीएम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर 10%-25% तक की छूट दे रहा है। इसमें उड़ान, रेल और बस की टिकट शामिल हैं। यात्रा कार्निवल सेल के



तहत, कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। ग्राहक घरेलू उड़ानों के साथ तकनीकी उड़ानों पर 15% तक की छूट, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 10% तक की छूट, और बस बुकिंग पर 25% तक की छूट का फायदा ले सकते हैं। यूपीआई का इस्तेमाल कर पेटीएम के जरिए ट्रेन बुकिंग की

जाती है, तो ट्रेन बुकिंग के लिए भुगतान गेटवे शुल्क नहीं होता है। नए गंतव्यों पर हर हफ्ते मिलेगी विशेष छूट पेटीएम ने बाकू और अल्मटी (कजाकिस्तान) जैसे अनोखे स्थानों में लोगों के बढ़ते रुझान को देख रहा है। यही वजह है कि कंपनी नए गंतव्यों पर हर हफ्ते विशेष छूट दे रही है। इस हफ्ते का गंतव्य बाकू है।

मई में फिर महंगी हुई वेज थाली, चिकन की कीमतों में गिरावट के बाद नॉन-वेज खाना सस्ता

क्रिसिल मार्केट इंटीलजेंस एंड एनालिसिस ने अपनी मासिक Rice Roti Rate रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में वेज थाली की कीमतों में 9 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दरअसल प्याज टमाटर और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से वेज थाली महंगी हुई है। वहीं नॉन-वेज थाली की कीमतों में 7 फीसदी की गिरावट आई।

नई दिल्ली। क्रिसिल मार्केट इंटीलजेंस एंड एनालिसिस ने अपनी मासिक Rice Roti Rate रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मई महीने में वेज थाली की कीमतों में 9 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दरअसल, प्याज, टमाटर और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से वेज थाली महंगी हुई है।

वहीं, नॉन-वेज थाली की कीमतों में गिरावट आई। पोल्ट्री की कीमतों में गिरावट आने की वजह से मांसहारी थाली में नरमी आई। क्रिसिल मार्केट इंटीलजेंस एंड एनालिसिस घर पर थाली तैयार करने की औसत लागत की गणना उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम भारत में प्रचलित इनपुट कीमतों के आधार पर करती है।

थाली की कीमतों में बदलाव का असर आम आदमी के खर्च पर पड़ता है। क्रिसिल की रिपोर्ट से अनाज, दालें, ब्रॉयलर, सब्जियां, मसाले, खाद्य तेल और रसोई गैस आदि की कीमतों के बारे में भी पता चलता है।

क्यों महंगी हुई वेज थाली

टमाटर, आलू और प्याज की कीमतों में सालाना आधार पर तेजी आई है, जिसकी वजह से शाकाहारी थाली की लागत में वृद्धि हुई। रबी के फसल में उल्लेखनीय गिरावट के कारण प्याज की कीमतों में तेजी आई थी। वहीं, पश्चिम बंगाल में पिछली झुलसा रोग और फसल क्षति के प्रतिकूल प्रभाव के कारण आलू की आवक में गिरावट के कारण कीमतों में वृद्धि हुई।

चावल की कीमत में साल-दर-साल 13% की वृद्धि हुई। वहीं, पिछले साल दालों के उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। चावल और दालों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से शाकाहारी थाली की कीमतों में साल-दर-साल में 21% की वृद्धि हुई।

इसके विपरीत, जीरा, मिर्च और वनस्पति तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे शाकाहारी थाली की लागत में और वृद्धि नहीं हुई।

सस्ती क्यों हो रही है नॉन-वेज थाली नॉन-वेज थाली की कीमत में पिछले साल से गिरावट आई। पिछले वित्तीय वर्ष के उच्च आधार पर ब्रॉयलर की कीमतों में सालाना 16% की गिरावट की वजह से नॉन-वेज थाली सस्ती हो गई। हालांकि, महीने-दर-महीने शाकाहारी थाली की कीमत 1% बढ़ी और नॉन-वेज थाली की कीमत 1% कम हुई। आलू की कीमतों में 9% की वृद्धि के कारण शाकाहारी थाली की कीमत में महीने-दर-महीने मामूली वृद्धि हुई, जबकि अन्य प्रमुख घटकों की लागत मोटे तौर पर स्थिर रही। नॉन-वेज थाली की कीमत कम हो गई क्योंकि ब्रॉयलर की कीमत 2% घट गई।

बाजार में तेजी, लेकिन थम नहीं रही रुपये में गिरावट, डॉलर के सामने इतने पैसे लुढ़का रुपया

परिवहन विशेष न्यूज

Dollar Vs Rupee गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय करेंसी 5 पैसे गिरकर बंद हुआ है। दरअसल सतारूढ़ भाजपा को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना न होने की वजह से यह गिरावट आई। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय करेंसी 83.40 पर खुली और सत्र के दौरान ग्रीनबैंक के मुकाबले इंडा-डे में 83.50 के निचले स्तर को छू गई। अंततः अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.49 (अंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 5 पैसे कम है।

नई दिल्ली। चुनावी नतीजों के बाद शेयर बाजार में तेजी आई। लेकिन, वहीं भारतीय करेंसी में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गुरुवार के कारोबारी सत्र में भारतीय करेंसी 5 पैसे गिरकर बंद हुआ है। दरअसल, सतारूढ़ भाजपा को लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलने की संभावना न होने की वजह से यह गिरावट आई। विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा कि कमजोर अमेरिकी मुद्रा और इक्विटी बाजारों में मजबूत रुख ने स्थानीय मुद्रा को समर्थन दिया। हालांकि निवेशक श्रृंखला को धोषित होने वाले आरबीआई की मौद्रिक नीति निर्णय से पहले चिंतित है। डॉलर और रुपये के बीच कारोबार

इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय करेंसी 83.40 पर खुली और सत्र के दौरान ग्रीनबैंक के मुकाबले इंडा-डे में 83.50 के निचले स्तर को छू गई। अंततः अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 83.49 (अंतिम) पर बंद हुई, जो पिछले बंद से 5 पैसे कम है।

पिछले कारोबारी सत्र बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 7 पैसे बढ़कर 83.44 पर बंद हुआ। शेयरखान बाय बीएनपी पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और एफआईआई (विदेशी संस्थागत निवेशकों) के बिकवाली देबाव के कारण रुपये में गिरावट आई। हालांकि, कमजोर अमेरिकी डॉलर और घरेलू बाजारों में सकारात्मक रुख से रुपये को निचले स्तर पर समर्थन मिला।



डॉलर इंडेक्स का क्या है हाल ?

दुनिया की बड़ी करेंसी के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा की मजबूती बताने वाला डॉलर इंडेक्स 0.03 प्रतिशत की गिरावट के साथ 104.18 पर आ गया। कच्चे तेल में आज फिर तेजी देखी जा रही है और यह 0.31 प्रतिशत बढ़कर 78.65 डॉलर प्रति बैरल पर है।

भारतीय शेयर बाजार में तेजी आज बीएसई सेंसेक्स 692.27 अंक या

0.93 प्रतिशत चढ़कर 75,074.51 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 201.05 अंक या 0.89 प्रतिशत बढ़कर 22,821.40 पर पहुंच गया। विदेशी निवेशक बुधवार को भारतीय इक्विटी के शुद्ध विक्रेता थे, क्योंकि उन्होंने शुद्ध आधार पर 5,656.26 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। एफआईआई ने नकद खंड में 21,012.72 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और 26,668.98 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची।

पिक्सल, सरवम AI और निरामा जैसे इंडियन स्टार्टअप को मिली डब्ल्यूईएफ टेक पाइनीयर्स लिस्ट में जगह

Pixxel Niramai और Sarvam AI सहित दस भारतीय स्टार्टअप ने गुरुवार को प्रकाशित World Economic Forums Technology Pioneers 2024 की लिस्ट में जगह बनाई है। सूची में शामिल अन्य भारतीय नामों में इंटरनेशनल बैटरी कंपनी बड़े आकार की रिचार्जबल प्रिज्मेटिक ली-आयन निकल मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी बना रही है एनएक्सटीवेव एआई-संचालित स्थानीय भाषा-आधारित कोडिंग पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है। आइए पूरी खबर के बारे में जान लेते हैं।

नई दिल्ली। Pixxel, Niramai और Sarvam AI सहित दस भारतीय स्टार्टअप ने गुरुवार को प्रकाशित World Economic Forum's Technology Pioneers 2024 की लिस्ट में जगह बनाई है। इस सूची में कुल 100 अग्रणी तकनीकी स्टार्टअप हैं जो स्वच्छ ऊर्जा समाधान, स्वास्थ्य सेवा इनोवेशन और जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और तंत्रिका प्रौद्योगिकी में प्रगति के लिए एआई में नई सफलताओं को लागू करने पर केंद्रित हैं। लिस्ट में शामिल ये कंपनियां

इस सूची में Airbnb, Google, Kickstarter और Spotify जैसे तकनीकी दिग्गज पहले से भी शामिल हैं। निरामाई शुरुआती फेज के कैसर का पता



लगाने के लिए एक नया एआई-बेस्ड परीक्षण विकसित कर रहा है, जो कि सस्ता, पोर्टेबल और गैर-आक्रामक है। कौन-क्या काम करता है ? पिक्सल भू-स्थानिक डेटा को कैप्चर करने के लिए हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजरी डेवलप कर रहा है, जबकि सरवम एआई भारतीय भाषाओं और उपयोग के मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके उपयोग के लिए आधार एआई मॉडल और प्लेटफॉर्म बना रहा है। भारतीय प्रवेशकों में एम्पीयरआवर भी शामिल है, जो डिस्पैच करने योग्य अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र बना रहा है और क्रॉपिन जो किसानों को उनके खेतों को जियो-टैग

करने, खेत के रिपोर्ट को डिजिटलाइज करने, फसल उत्पादकता की निगरानी करने और खेत की गतिविधि में सुधार करने में मदद करने के लिए एक खेत निगरानी और प्रबंधन समाधान विकसित कर रहा है। एंटी भारतीय स्थानीय भाषाओं में सीखने और कौशल विकास कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान कर रही है, जबकि हेल्थप्लक्स स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एआई-संचालित इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर विकसित कर रही है। लिस्ट में इन कंपनियों का भी नाम सूची में शामिल अन्य भारतीय नामों में इंटरनेशनल बैटरी कंपनी बड़े आकार की रिचार्जबल प्रिज्मेटिक ली-आयन निकल

मैग्नीज कोबाल्ट बैटरी बना रही है, एनएक्सटीवेव एआई-संचालित, स्थानीय भाषा-आधारित कोडिंग पाठ्यक्रम प्रदान कर रही है और सट्रिंग बायो जोएचजी गैसों से कृषि, पशु आहार और मानव पोषण के लिए अंगुली पीढ़ी की सामग्री का उत्पादन कर रही है। 100 प्रौद्योगिकी अग्रदूतों में 23 देशों के स्टार्टअप शामिल हैं, जिनमें से एक तिहाई का नेतृत्व एक महिला मुख्य कार्यकारी कर रही है। भारत से पिक्सल सहित 9 अंतरिक्ष कंपनियां, चार न्यूरोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप और भारत से एम्पीयरआवर और इंटरनेशनल बैटरी कंपनी सहित स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली चार कंपनियां हैं।

एप्पल को पीछे छोड़कर Nvidia बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, 3 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंचा M-Cap

दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक बार फिर से फेरबदल हो गया है। अब सेमीकंडक्टर चिप (Semiconductor Chip) बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia) दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। Nvidia का एम-केप (Market Cap) से आगे बढ़ गया। एनवीडिया कॉर्प के शेयरों (Nvidia Corp Share) में तेजी आई थी जिसके बाद कंपनी के मार्केट-केप में भारी उछाल आया।

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक बार फिर से फेरबदल हो गया है। अब सेमीकंडक्टर चिप (Semiconductor Chip) बनाने वाली कंपनी एनवीडिया (Nvidia) दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है।

पहले दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी के पायदान पर आईफोन (iPhone) बनाने वाली एप्पल (Apple) कंपनी थी।

बुधवार को एनवीडिया कॉर्प के शेयरों (Nvidia Corp Share) में तेजी आई थी, जिसके बाद कंपनी के मार्केट-केप में भारी उछाल आया। अगर कंपनी के शेयर की बात करें तो बुधवार को एनवीडिया कॉर्प के स्टॉक 60.03 डॉलर या 5.16 फीसदी की तेजी के साथ 1,224.40 डॉलर (करीब 1,86,958 रुपये) पर बंद हुआ।

स्टॉक में तेजी के बाद एनवीडिया कॉर्प का एम-केप (nvidia market cap) 3.01 ट्रिलियन डॉलर (करीब 251 लाख करोड़ रुपये) हो गया। वहीं, आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी का बाजार पूंजीकरण 3 ट्रिलियन डॉलर है। बुधवार को एप्पल के शेयर 195.87 डॉलर पर बंद हुआ। एनवीडिया के शेयर के परफॉर्मंस एनवीडिया के शेयर ने पिछले 5 कारोबारी सत्र में 6.93 फीसदी का रिटर्न दिया। वहीं, 6 महीने में कंपनी के शेयर ने 169.08 फीसदी का रिटर्न दिया। साल 2024 में अभी तक एनवीडिया के शेयर में 154.19 प्रतिशत की तेजी आई। अगर पिछले 1 साल की बात करें तो एनवीडिया का शेयर ने 216.76 प्रतिशत का पॉजिटिव रिटर्न दिया। एनवीडिया के शेयर में आई तेजी के बाद एनवीडिया के



सीईओ जेन्सेन हुआंग की नेतृत्व में भी इजाफा हुआ है। जेन्सेन हुआंग की नेतृत्व में 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा की तेजी आई। अब उनकी नेतृत्व 107.4 बिलियन डॉलर हो गई।

साल 2002 में भी एप्पल से आगे बढ़ा था एनवीडिया

वर्ष 2002 में भी एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन एप्पल से आगे बढ़ गया था। उस साल इन दोनों कंपनियों के एम-केप में लगभग 83,000 करोड़ रुपए से कम का अंतर था। साल 2007 में एप्पल ने पहला आईफोन (iPhone) लॉन्च किया था। आईफोन के लॉन्च के बाद एप्पल के बाजार पूंजीकरण तेजी से बढ़ा। एनवीडिया के बारे में

एनवीडिया सेमीकंडक्टर चिप मैन्यूफैक्चर करती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फर्म है। भारत में NVIDIA के चार इंजीनियरिंग डेवलपमेंट सेंटर हैं। एनवीडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है। दुनिया में इस कंपनी को ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) के डिजाइन और मैन्यूफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। एनवीडिया की स्थापना साल 1993 में जेन्सेन हुआंग, कर्टिस प्रीम और क्रिस मालाकोव्स्की ने की थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में है।

मोदी गठबंधन के अग्निपथ पर अब 9 को लेगे शपथ

परिवहन विशेष न्यूज

एसडी सेठी। एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बड़ा फेरबदल हुआ है। वह अब 8 जून की जगह 9 जून को एनडीए गठबंधन के प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होने जा रहे हैं। मोदी के राजतिलक की तैयारी जोरों पर है। पहले वह 8 जून को शपथ लेने वाले थे। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी इस बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद देश के दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बन जाएंगे जो लगातार तीन बार प्रधानमंत्री चुने गए हों। इससे पहले जवाहर लाल नेहरू लगातार तीन बार प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। पीएम मोदी देश के दूसरे और भाजपा से पहले पीएम होंगे, जिन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह इस बार चुनाव परिणाम आने के 5 वें दिन आयोजित किया जा रहा है। 2019 में शपथ ग्रहण कार्यक्रम 7 दिन बाद हुआ था। इसके अलावा 2014 में सरकार बनने पर 10 दिन बाद संपन्न हुआ था। पीएम मोदी के नेतृत्व में इस बार एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। 293 सीटों के साथ एनडीए ने शानदार जीत हासिल की है। मगर चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने अपनी-अपनी शर्तें लादने दी हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार ने अग्निपथ, आचार संहिता,



(सीसीए), समेत तीन मंत्रियों के पद की डिमांड कर दी है। इनमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय समेत लोकसभा स्पीकर की मांग कर रहे हैं। इसी तरह टीडीपी ने भी स्पीकर, कृषि मंत्रालय की डिमांड रख दी है। उधर भाजपा ने

भी साफ कर दिया ज बड़े व भारी मंत्रालय जिनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, समेत अन्य मंत्रालय अपने पास रखने की चर्चा है। दरअसल शपथ ग्रहण में देरी होने की वजह भी ये ही बताई जा रही है।

दूसरी ओर इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं ने सभी दलों की बैठक कर वेट एंड वॉच के लिए कहा है। उनका मानना है कि एनडी लंबा चलने वाला नहीं है। जब भी मौका मिलेगा हम सरकार बना लेंगे।

भाजपा सतर्क थी, लेकिन सरकार बनाने का दावा पेश करने की पेचीदगियां समझ रहे थे खरगे और पवार....

परिवहन विशेष न्यूज

विपक्ष के सांसदों की संख्या भाजपा से भी कम है। इस तरह से 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसदों वाला दल भी भाजपा ही है। विपक्षी गठबंधन और एनडीए, दोनों द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे पहले भाजपा को ही आमंत्रित करतीं। यह स्थिति आने पर विपक्षी गठबंधन को फजीहत का सामना करना पड़ता।

नई दिल्ली। इंडिया गठबंधन ने समझदारी भरा फैसला लिया। 5 जून को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राष्ट्रीय स्तर के एक नेता ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार सरकार बनाने का दावा पेश करने से जुड़ी सभी पेचीदगियां समझ रहे थे। पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को भी पता था कि सहयोगी दल सरकार बनाने का भले दावा करें, लेकिन कई

तकनीकी रुकावटें हैं।

कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि भाजपा तो सतर्क थी। उसे लग रहा था कि विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की पहल कर सकता है। बताते चलें कि चुनाव नतीजा आने से पहले भाजपा और केंद्र के रणनीतिकार 9 जून को ही शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सूत्र की मानें तो चुनाव नतीजा आने के बाद से भाजपा जल्दबाजी में आ गई। वह तेजी से कई निर्णय ले रही थी। भाजपा मुख्यालय के भी एक नेता ने 9 जून के बजाय 8 जून को ही तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ की संभावना जता दी थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन का निर्णय आने के बाद तारीख दोबारा बदलकर 9 जून कर दी गई।

क्या थी विपक्षी गठबंधन के रास्ते में सरकार बनाने में पेचीदगियां?

विपक्ष के सांसदों की संख्या भाजपा से भी कम है। इस तरह से 18वीं लोकसभा में सबसे अधिक सांसदों वाला दल भी भाजपा ही है।

विपक्षी गठबंधन और एनडीए, दोनों द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश करने की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे पहले भाजपा को ही आमंत्रित करतीं। यह स्थिति आने पर विपक्षी गठबंधन को फजीहत का सामना करना पड़ता। मल्लिकार्जुन खरगे और शरद पवार का मानना था कि संयम, अनुशासन और मर्यादा की राजनीति ठीक है। सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसी स्थिति आना सही नहीं होगा। विपक्षी गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 272 की जरूरी संख्या तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं था। यह दूसरी बड़ी पेचीदगी थी। एमके स्टालिन को भी सहयोगी दलों के साथ आने को लेकर चिंता थी।

पटना से दिल्ली की उड़ान में तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ आए थे। नीतीश ने लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही विपक्ष का साथ छोड़ा था। इसलिए नीतीश कुमार और जद(यू) के इतना जल्द विपक्ष के साथ जुड़ने की कोई संभावना नहीं दिखाई दी।

लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा के साथ ही 16 मार्च से लागू आदर्श आचार संहिता हटा ली गई है. निर्वाचन आयोग ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया

परिवहन विशेष न्यूज

इसी के साथ रुके हुए सरकारी काम अब रफ्तार पकड़े लेंगे.

केंद्रीय कैबिनेट सचिव और राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में निर्वाचन आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से हटा ली गई है.

क्या होती है आदर्श आचार संहिता? आदर्श आचार संहिता सभी हितधारकों द्वारा

सहमत और चुनावों के दौरान लागू परंपराओं का एक दस्तावेज है. राजनीतिक दल स्वयं चुनाव के दौरान अपने आचरण को नियंत्रित रखने और संहिता के भीतर काम करने पर सहमत हुए हैं.

यह निर्वाचन आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिये गए जनादेश को ध्यान में रखते हुए मदद करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति देता है.

कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं हालांकि इसे कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं

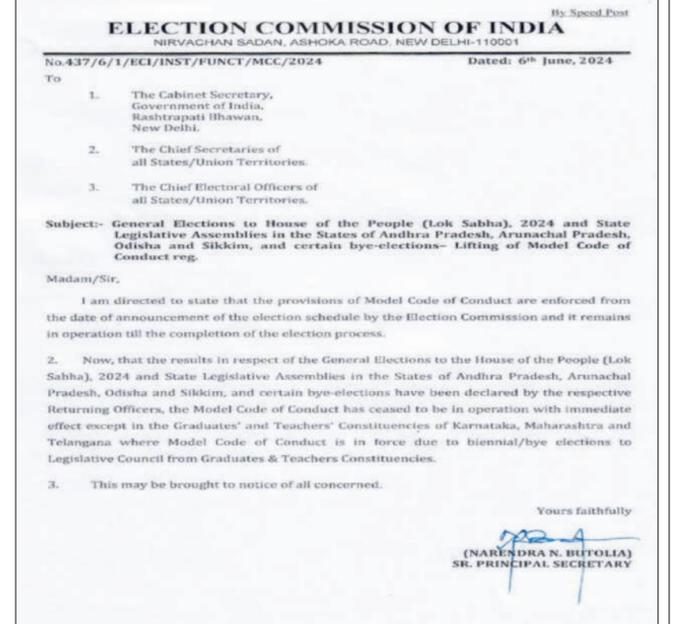
है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने कई मौकों पर इसकी पवित्रता को बरकरार रखा है. आयोग संहिता के किसी भी उल्लंघन की जांच करने और सजा सुनाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है.

आचार संहिता की शुरुआत 1960 में केरल में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जब प्रशासन ने राजनीतिक दलों के लिए एक आचार संहिता तैयार करने की कोशिश की. यह संहिता पिछले 60 वर्षों में विकसित होकर अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंची है.

इन नियमों का करना होता है पालन भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार, आदर्श

आचार संहिता में कहा गया है कि केंद्र और राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे प्रचार के लिए अपने आधिकारिक पदों का उपयोग न करें. आचार संहिता लागू रहने के दौरान मंत्री और अन्य सरकारी प्राधिकरण किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते.

ऐसी किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करती हो और चुनाव आचार संहिता लागू होने की स्थिति में मंत्री प्रचार के मकसद से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते.



दिल्ली में हमेशा के लिए खत्म हो सकता है जल संकट, अगर किए जाएं ये जरूरी काम

दिल्ली में बीते कुछ सालों से जैसी ही गर्मी शुरू होती है। ठीक वैसे ही जल संकट की गंभीर समस्या भी शुरू हो जाती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इसका कोई ठोस समाधान निकले। जिससे दिल्लीवासियों को पानी की किल्लत से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। इसलिए आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जहां से इस समस्या का समाधान हो सकता है।

नई दिल्ली। दिल्ली में बीते कुछ सालों से जैसी ही गर्मी शुरू होती है। ठीक वैसे ही जल संकट की गंभीर समस्या भी शुरू हो जाती है। इसी बीच गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दायर की गई याचिका पर बड़ा फैसला दिया। जिसमें अदालत ने हिमाचल प्रदेश को तत्काल प्रभाव से 127 क्यूसेक पानी देने को कहा है। जिससे दिल्ली वालों की प्यास बुझ सके, लेकिन आज हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिससे दिल्ली में हमेशा के लिए ये समस्या खत्म हो जाए।

कहने नहीं, काम करने से दूर होगा जल संकट 1000 एमजीडी पेयजल उपलब्ध कराने का दावा करता है जल बोर्ड, इसमें से लगभग 52 प्रतिशत चोरी हो जाता है या बर्बाद हो रहा है। 20 प्रतिशत बर्बादी रोकने पर 200 एमजीडी पानी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा।

गर्मी के दिनों में स्वाभाविक रूप से पानी की खपत बढ़ जाती है। इस कारण मांग बढ़ती है। बड़ी हुई मांग पूरी करने के लिए ठोस तैयारी नहीं होती है। इसका परिणाम है कि दिल्ली में कई स्थानों पर पानी की किल्लत हो रही है। अब समस्या ये है कि वर्तमान सरकार इस पर राजनीति तो खूब कर रही है, लेकिन पानी की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास नहीं हो रहा।

पहले सिर्फ दिल्ली सब ग्रॉस (डीएसबी) नहर के माध्यम से हरियाणा से पानी मिलता था। कच्ची नहर में होने वाले रिसाव से लगभग 25 प्रतिशत पानी बर्बाद हो जाता था। इस समस्या के समाधान के लिए पक्की नहर कैरियर चैनल कनाल (सीएलसी) बनाया गया। इसके लिए दिल्ली ने हरियाणा सरकार को लगभग पांच सौ करोड़ रुपये दिए थे।

अदालत के निर्देश पर हरियाणा ने वर्ष 2014 में इस नहर के माध्यम से दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी देना शुरू किया है। इससे द्वारका, बबना व ओखला तीन जल उपभोग संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) शुरू हो सका है। उसके बाद से पानी की उपलब्धता बढ़ाने का कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया गया।

मुनक नहर में हरियाणा से साढ़े पांच सौ से अधिक क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है जिससे कि 425 क्यूसेक

पानी वजीराबाद जलाशय में पहुंच सके। चंद्रावल व वजीराबाद प्लांट के लिए इतना पानी जरूरी है। मुनक नहर से ड्रेन नंबर आठ से पानी पल्ला के पास यमुना में गिराया जाता है। यमुना से पानी वजीराबाद जलाशय में आता है।

एक दशक से इस जलाशय की सफाई नहीं हुई है। इस कारण गाद जमा होने से जलाशय की भंडारण क्षमता कम हो गई है। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रत्येक दो से तीन वर्ष में पानी सफाई करनी है। जल बोर्ड यह काम नहीं कर रहा है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा को दोष दिया जा रहा है।

मानसून में बाढ़ आने पर नदी के किनारों में पानी जमा हो जाता है। सर्दी के मौसम में पानी रिसकर अपने आप यमुना में आता रहता है, फरवरी तक इससे भी कुछ पानी मिल जाता है। गर्मी के दिनों में सभी जगह पानी की कमी होती है। इस कारण हरियाणा भी समझौते से अधिक पानी नहीं देता है। वाष्पीकरण से नहर से आने वाली पानी का नुकसान भी बढ़ जाता है।

नदी के किनारों में जमा पानी भी समाप्त हो जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ वर्ष पहले यमुना किनारे तालाब बनाने की घोषणा की थी। कुछ तालाब बनाए भी गए थे परंतु उनका रखरखाव नहीं होने के कारण बाढ़ आने से नष्ट हो गए। यदि यमुना किनारों पर पानी भंडारण की व्यवस्था होती तो गर्मी के मौसम में इस तरह की परेशानी नहीं होती।

दिल्ली जल बोर्ड एक हजार एमजीडी पेयजल उपलब्ध कराने का दावा करता है। इसमें से लगभग 52 प्रतिशत या तो चोरी या बर्बाद हो रहा है। 20 प्रतिशत बर्बादी रोकने पर 200 एमजीडी पानी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इसके लिए निगरानी तंत्र को बेहतर बनाने के साथ उपभोक्ताओं को जागरूक करना होगा। कई स्थानों पर पाइपलाइन टूटी हुई हैं जिससे पानी बर्बाद हो रहा है।

कई स्थानों पर जमीन के अंदर रिसाव होता रहता है जिससे होने वाले नुकसान का पता नहीं चलता है। यूरोप, अमेरिका, सिंगापुर, जापान में बर्बादी रोकने के लिए प्रत्येक स्तर पर पानी का आडिट होता है। उपभोक्ताओं द्वारा पानी की खपत को भी आडिट किया जाता है जिससे घरों में होने वाली बर्बादी का पता लगाकर उसे रोकने के कदम उठाए जाते हैं।

दिल्ली में 70 प्रतिशत पानी का उपयोग सिंचाई, वाहनों की सफाई, शौचालय जैसे गैर पेयजल के लिए होता है। वहीं, एसटीपी से मिलने वाला पानी नाले में बहाया जा रहा है। कई स्थानों पर लोग बोरिंग कर सिंचाई और अन्य काम के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जिससे भूजल स्तर नीचे गिर रहा है। यदि एसटीपी से मिलने वाले

शोधित जल का उपयोग गैर पेयजल कार्यों में किया जाए तो पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी।

एसटीपी से मिलने वाले 550 एमजीडी शोधित जल में से सिर्फ 90 एमजीडी का उपयोग हो रहा है। इस पानी का उपयोग सिंचाई, वाहनों को धोने, मेट्रो व रेलवे के कार्यों में, सड़कों पर छिड़काव व अन्य कार्यों में होना चाहिए। रिज एरिया में इस पानी को संग्रहित किया जाना चाहिए जिससे भूजल स्तर बढ़ेगा। इन कार्यों के मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है।

राजधानी में फिलहाल 650 एमजीडी पानी ही सुधारा जा रहा है। इसकी गुणवत्ता भी ऐसी नहीं है कि उसे यमुना में इस्तेमाल किया जा सके। दिल्ली में हर गर्मियों में पानी की किल्लत का यह प्रमुख कारण है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता और गुणवत्ता ठीक कर ली जाए, तो पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। वर्तमान में दिल्ली में जो समस्या दिख रही है, उसका कारण एकत्र किए गए पानी की कमी है। गर्मियों में यह लाजमी भी है।

यहां का पानी वाष्प बन जाता है। भूजल का स्तर भी नीचे चला जाता है। पूरे हालात पर नजर डालें तो दिल्ली दो दिहाई पानी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। फिलहाल समस्या का समाधान नहीं है और उत्तर प्रदेश व हरियाणा अगर 30 से 40 एमजीडी पानी दें, तो ही जनता की प्यास बुझाई जा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्यूबवेल के जरिये पानी टैंकर से लोगों तक पहुंचाया जाए, यही तरीका सरकार अपना भी रही है। लेकिन, नलों में पानी पहुंचाने के लिए उन्हें स्थायी समाधान चाहिए।

वर्तमान में दिल्ली में हर साल औसत 1,170 एमजीडी पानी की जरूरत होती है। फिलहाल लगभग 1,000 एमजीडी पानी का उत्पादन हो रहा है। इसमें 20 प्रतिशत लाइन से बाहर चला जाता है। कुल 25 प्रतिशत पानी कम उपलब्ध हो रहा है। गर्मियों में आपूर्ति घटने से अब समस्या विकराल हो गई है। वर्तमान में जो पानी राजधानी के लोगों को पहुंचाया गया है, उसका 87 प्रतिशत नदियों से आता है। शेष 13 प्रतिशत में नौ प्रतिशत भू-गर्भ का जल है और चार प्रतिशत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दोबारा उपयोगी बनाकर दिया जा रहा है।

नदियों के 87 प्रतिशत जल में 30 प्रतिशत अपर गंगा कैनाल से, 32 प्रतिशत सतलज और यमुना का मुनक से व 37 प्रतिशत यमुना से लिया जा रहा है। बरसात में 1063 एमजीडी पानी प्राकृतिक तौर पर मिलता है, लेकिन उसे एकत्र नहीं किया जा पाता। पांच राज्यों के समझौते के तहत 250 एमजीडी उपचारित किया हुआ पानी यमुना में सरकार को डालना ही है। इसलिए दूसरा

रास्ता भी खोजना होगा। सरकार बाढ़ के मैदानी इलाकों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। राजधानी में 97 किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ का मैदानी क्षेत्र है।

इसमें फिलहाल 12 किलोमीटर क्षेत्र में ट्यूबवेल लगाकर पानी निकाला जा रहा है, जबकि इस पूरे क्षेत्र का इस्तेमाल कर पानी लिया जा सकता है। हालांकि, यह विज्ञानी तरीके से होगा। कितनी मात्रा में पानी निकालना है, ट्यूबवेल के बीच समुचित दूरी रखनी है। नदी से भी समुचित दूरी रखकर ट्यूबवेल खोदने होंगे।

पूरे क्षेत्र का एक डिजाइन तैयार करना होगा। इसके बाद यहां से पानी की आपूर्ति गर्मियों में की जा सकती है। जब बरसात आएगी तो पूरा इलाके में पानी भर जाएगा और जितना जल दोहन किया गया है, वो बराबर हो जाएगा। अभी वजीराबाद से ऊपर पल्ला क्षेत्र में 100 नलकूप सरकार ने लगाए हैं। इनसे 30 एमजीडी पानी हर रोज निकाला जाता है। मानसून में इस इलाके में पानी का स्तर उठना ही हो जाता है, जितना उससे पहले था।

इनके लगने के बाद से 22 वर्षों में दो लाख 41 हजार एमजीडी पानी निकाला जा चुका है। पर, भूजल के स्तर में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहां से 60 एमजीडी पानी निकाला जा सकता है। ऐसा ही यमुना विहार और ओखला बैराज के मैदानों में भी किया जा सकता है। सरकार इन नलकूपों से 100 एमजीडी तक पानी निकाल सकती है।

इससे समस्या का समाधान हो सकता है। यह तो वर्तमान समस्या की बात है, भविष्य में दिल्ली की आबादी और बढ़ेगी। तब लोगों को 1,332 एमजीडी पानी की जरूरत होगी। उसके लिए सरकार के पास फिलहाल कोई योजना दिखाई नहीं देती।

200 एमजीडी लाइन लास को हटा लें, तो 532 एमजीडी की जरूरत भविष्य में पड़ेगी। नदियों से पानी नहीं ले सकते। नलकूपों से कुछ भार कम जरूर होगा, लेकिन 300 एमजीडी पानी के उत्पादन की जरूरत पड़ेगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से साफ पानी का उत्पादन कर इसे बढ़ाया जा सकता है। उसके लिए सरकार को स्थायी और मजबूत योजना बनानी होगी।

राजनीति का शोर, पानी ले गए 'चोर' दिल्ली में जल संकट का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि पानी के टैंकर के इंतजार में कतार भोर से लगती है और आते ही कुछ इलाकों में तो महज 10-15 मिनट में टैंकर खाली हो जाता है। जल संकट में जो रही राजधानी के दक्षिणी से पूर्वी तक ऐसी स्थिति मिल जाएगी। एक तरफ एक टैंकर 10 मिनट में खाली, दूसरी तरफ राजनेताओं के संरक्षण में फलम हो रहे जल माफिया के कारोबार ने दिल्ली के जल संकट को खत्म नहीं होने दिया।



बालाजी नगर स्थित श्री आईजी गौशाला में अभावस्था के अवसर पर श्री आईजी गौशाला के अध्यक्ष मंगलाराम पंवार, सह सचिव ढगलाराम सेपटा, अर्जुनलाल बर्वा, भंवरलाल मुलेवा, पारसमल शर्मा, बाबूलाल मुलेवा, गोपाराम मुलेवा, भगाराम मुलेवा, भोजन प्रसादी लामाथी पवन हाम्बड, भीकाराम पंवार, चेलाराम पंवार, बगदाराम बर्वा नवरल पंवार, प्रकाश हाम्बड, राजेश हाम्बड, पांचाराम पंवार चन्दु पंवार, राजू पंवार, गोतम पंवार, आईमाता जी भजन मण्डली बालाजी नगर द्वारा भजन प्रस्तुत किया। गौभक्तों ने भजनों का आनंद लिया। हेल्थ चेकअप कैप आयोजित किया। इसमें कार्यकारिणी सदस्य एवं महिला मंडल एवं गौभक्त ने गो सेवा की।

बीएसकेवाई कार्ड बैन के नाम पर स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही एक सामाजिक और कानूनी अपराध: मनमोहन सामल

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

भुवनेश्वर : आम चुनाव-2024 के नतीजे जारी होने के बाद बीजू स्वास्थ्य कल्याण कार्ड (बीएसकेवाई) को लेकर कई शिकायतें आ रही हैं। विभिन्न मीडिया में ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि राज्य के कुछ निजी अस्पताल बीएसकेवाई कार्ड बंद होने की बात कहकर मरीजों को बिना इलाज किये लौटा रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है," प्रदेश अध्यक्ष श्री मनमोहन सामल ने कहा। मरीजों और बीमारियों की कोई जाति, धर्म या जाति नहीं होती। आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हर सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बलवाना एक सतत प्रक्रिया है। लोगों के मन में द्वंद पैदा करना और उन्हें चिकित्सा सेवाओं से दूर रखना एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। प्रदेश अध्यक्ष श्री सामल ने प्रशासन से ऐसे सामाजिक अपराधों से बचने और ओडिशा के लोगों को उचित और बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने को कहा।